प्रिय मित्रो,

मई, २००८ में यूपीए ने अपनी सरकार के चार साल के कार्यकाल पूरे कर लिए। हर साल रिपोर्ट कार्ड पेश करने की अवधारणा किसी भी सरकार की उपलब्धियों के बारे में आमजन को सूचित करने का अनोखा तरीके है ताकि वे उसकी उपलब्धियों का लेखा-जोखा कर सकें और यह तय कर सकें कि सरकार ने अपने गठन के समय जो लक्ष्य घोषित किए थे उनको पूरा करने की दिशा में सक्रिय है कि नहीं।

जब यूपीए सत्ता में आया था उसने भारत के लोगों द्वारा तय लक्ष्यों की पहचान की थी। जनादेश पंथ निरपेक्ष मूल्यों को फिर से कायम करने के लिए, जिनका क्षरण किया जा रहा था, खेती तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार तेज करने के लिए, चतुर्दिक आर्थिक विकास तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए तथा इससे भी बढ़कर सर्वाधिक गरीब एवं कमजोर वर्ग को अधिकार संपन्न बनाने के लिए था।

यूपीए के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का निर्धारण इन्हीं मकसदों को तथा अन्य मकसदों को पूरा करने के ख्याल से किया गया है।

लोगों के समक्ष पेश वार्षिक रिपोर्ट, हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के योग्य नेतृत्व में यूपीए सरकार के ४८ महीनों के कार्यों का वास्तविक दस्तावेज है। अपनी तथा आप लोगों की तरफ से सरकार की उपलब्धियों के लिए उनको मैं बेहिचक हार्दिक बधाई देती हूं। ऐसा संयोग ही है कि हमें ऐसा नेता मिला है जिनका लोक-लुभावने भाषण की जगह काम खुद बोलता है।

देश कीमतें बढ़ने के कारण कठिन स्थिति से गुजर रहा है। कीमतों को काबू रखने की पूरी कोशिशों के बावजूद वैश्विक घटनाक्रम से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अपूर्व बढ़ोतरी ने विश्व की हर अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जब तक कीमत वृद्धि का सवाल तेल कंपनियों के अस्तित्व के लिए खतरनाक नहीं बना तब तक कीमत बढ़ाने से बचते रहे। तब भी हमने तेल की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की है। हमारे आह्वान पर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने राज्य के करों में समंजन कर कीमत में बढ़ोतरी के बोझ को कम करने की व्यवस्था की है।

हमने अपने किसानों तथा गांव के लोगों का ज्यादा ख्याल रखा है। हमारे अग्रणी महत्व के कार्यक्रम इस तरह से तय किए गए हैं ताकि हमारी उपलब्धियों के फल गांव स्तर के सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचे। हम लोगों ने महिलाओं तथा बच्चों के हितों पर भी ज्यादा जोर डाला है। हम लोग महिलाओं को अपने प्रशासन के फैसला लेनेवाले निकायों में शामिल करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम लोग अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा देने के लिए कृतसंकल्प हैं। अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों की खास जरूरतों को पूरा करने के ख्याल से अनेक विकास कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उससे अधिक कोशिश करने की जरूरत है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल में हम लोगों को साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उन वायदों को भी पूरा करना है जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं।

इससे भी अधिक यह कार्यनीति बनाने की जरूरत है कि यूपीए सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी जानकारी सुनिश्चित रूप से आम लोगों को भी मिले ताकि वे कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने के लिए अपनी सही पसंद तय कर सकें।

कांग्रेस में श्रणिक चुनावी हारों से सबक लेने की क्षमता है। यह नयी चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकती है।

कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के मद्देनजर हमेशा इससे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें भी लोगों की रहती हैं। बुनियादी स्तर पर एक ठोस तथा जनता की जरूरतों के प्रति सजग संगठन ही कांग्रेस का संदेश जनता तक पहुंचाएगा। हमें पार्टी को सुदृढ़ करना है और कांग्रेसजनों तथा महिला कर्मियों को हर स्तर के लोगों के साथ जीवंत संपर्क कायम करना है। आनेवाले महीनों के दौरान हमें इन्हीं परीक्षणों से गुजरना है।

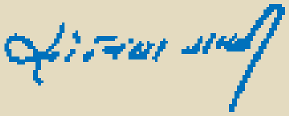

कांग्रेस संदेश

हिन्दी, अंग्रेजी में प्रकाशित मासिक पत्रिका

वर्ष 10, अंक 10, जून, 2008

संपादक मंडल

सलमान खुर्शीद

सर्वजीत सिंह

संपादक

अनिल शास्त्री

सहयोगी संपादक

पंकज शर्मा

डा. रवणी ठाकुर

संपादकीय दल

राम नरेश सिन्हा

रतन फ्रांसिस

प्रबंधक (प्रशा. एवं वितरण)

कमल साहू

डिजाइन

बेन्चमार्क ग्राफिक्स, कमल साहू

संपादकीय कार्यालय

कांग्रेस संदेश, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,

२४ अकबर रोड, नयी दिल्ली-११००११

फोन : २३०१६०८० फैक्स : २३०१७०४७

प्रकाशक

मोतीलाल वोरा, संदेश ट्रस्ट,

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

मुद्रक

चार दिशाएं प्रिंटर्स: जी-४०, सेक्टर-३,

नोएडा-२०१३०१ में मुद्रित एवं प्रकाशित

वैबसाइट

www.congresssandesh.com

सदस्यता शुल्क

मासिक	10 रूपये
वार्षिक	100 रूपये
द्विवार्षिक	175 रूपये
त्रिवार्षिक	250 रूपये

कृपया चेक / ड्राफ्ट 'संदेश ट्रस्ट' के नाम से भेजें

दिल्ली से बाहर के चेक २५ रूपए अतिरिक्त राशि जोड़कर भेजें। चेक/ड्राफ्ट "संदेश ट्रस्ट", २४ अकबर रोड, नयी दिल्ली-११०००१ के नाम ही भेजें।

कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण

यूपीए सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा करने पर कांग्रेस अध्यक्ष तथा यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे कार्यक्रमों का अच्छा प्रभाव लोगों के जीवन पर देखा जा सकता है 5

प्रधानमंत्री का भाषण

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार अब तक जनता से किए गए वायदों को काफी हद तक पूरा करने में समर्थ रही है जो उसने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में चार साल पहले किया था 6

कवर स्टोरी

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा है कि यूपीए सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान हमने सर्वनिहित विकास के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया है 8

कांग्रेस अध्यक्ष का दौरा

कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने गुवाहाटी की रैली में कहा है कि इतिहास के पन्नों में असम के किसानों की मेहनत, ईमानदारी तथा बहादुरी की चर्चा है 22

कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी का प्रस्ताव 23

राज्यों पर नजर

राजीव गांधी को श्रद्धांजलि 24

पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि 26

समाचार अग्रिम संगठनों से 27

राजीव गांधी ग्रामीण क्रिकेट 29

महिला कांग्रेस रिपोर्ट 29

पूर्व सैनिक विभाग की रिपोर्ट 30

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की डायरी 31

फोटोफाईल 32

जब कभी श्री नरेन्द्र मोदी कोई बयान देते हैं, उससे पंथनिरपेक्ष जनतंत्र के निर्माण संबंधी ढांचे परे ही खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए उसे एक चिंतित नेता के आक्रोश भरी आवाज कहकर नहीं नकारा जा सकता। श्री मोदी के लिए यह भाजपा की ऐसी मांग को नये शब्दों में अभिव्यक्त करना हो सकता है, जो उस भारतीय संविधान के मूलाधार पर ही प्रहार करना चाहता है जिसे हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने अपनाया था। यदि वास्तव में भाजपा चाहती है कि संविधान में संशोधन किया जाए तो उसके लिए उचित माध्यम संसद ही है, न कि अलग किस्म के ऐसे नेता की जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भावना भड़काने वाला भाषण देता रहता है।

वह एक अलग किस्म के नेता हैं, यह बात उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में ही साबित हो चुकी है। मुख्यमंत्री के रूप में वह समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रहार कर चुके हैं जिससे एक खास अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आतंक की स्थिति पैदा हो गई थी। उनके बयान की आलोचना करने की बजाय भाजपा ने उसके प्रति नरम रुख अपनाते हुए उनका बचाव करने की कोशिश की। भारत का संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में से एक है। यह वास्तविक जनतंत्र तथा सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यह उन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और जो छह दशक से समय की कसौटी पर खरा साबित हुआ है। यह तथ्य अपने पड़ोसी देशों की स्थिति पर एक नजर डालने से सही साबित हो जाएगा जहां जब उसके संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो उन देशों के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो गया।

श्री मोदी आसानी से यह भूल जाते हैं कि इसका श्रेय केन्द्र को ही है जिसने दूसरे राज्यों की तरह उनके राज्य में भी बुनियादी ढांचा तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरु कराई जिनसे गुजरात के अध्यवसायी लोगों की समृद्धि को बल मिला, जिस उपलब्धि पर श्री नरेन्द्र मोदी गर्व करते नहीं थकते। क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में वास्तव में ऐसा कोई नया काम किया है जिससे समृद्धि में और वृद्धि हुई? वह सिर्फ अगला लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सस्ती लोकप्रियता वाले मुद्दे उठाते रहते हैं। इस मामले में वह पारपंरगत हैं। नहीं तो इस मुद्दे पर उन्होंने केन्द्र में अपनी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बहस छेड़ दी होती।

श्री मोदी, हमें यह यकीन है कि जनता आपकी इस मंशा को खूब समझती हैं!

संपादक

उर्दू में भी संदेश छापें

मुझे पार्टी के मुखपत्र "कांग्रेस संदेश" को पढ़कर बहुत खुशी हुई। पत्रिका काफी सूचनाप्रद थी। इससे नयी दिल्ली तथा देश के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की जारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। मैं जमशेदपुर में ऑल इंडिया सोनिया गांधी प्रचार दल का महासचिव हूं। यदि यह पत्रिका उर्दू भाषा में भी प्रकाशित हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि अधिकतर अल्पसंख्यक इस भाषा को समझते हैं।

– मुहम्मद हाफिज,
जमशेदपुर, झारखंड

ऋण माफी सीमा बढ़ाने का स्वागत

वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम् द्वारा ऋण माफी की राशि में २० प्रतिशत की बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी की इस विचारधारा की द्योतक है कि कांग्रेस को अपने किसानों की चिंता है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की उसे समझ है और आर्थिक विकास पर सरकार के जोर का अब भी मुख्य महत्व है। बजट में किसानों की ६०,३१४ करोड़ रूपये की ऋण माफी की राशि बढ़ाकर ७१,६८० करोड़ रूपये की गई है। इसका हर एक आदमी ने स्वागत किया है।

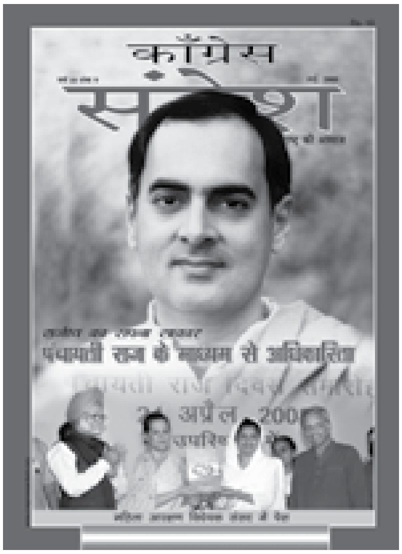

– राहुल स्वामी,
जयपुर, राजस्थान

प्रेरक लेख

पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सचिव कैप्टन प्रवीण दावर का लेख पढ़ा। यह लेख काफी प्रेरक था। इससे पंडित मोतीलाल नेहरू के अनेक त्यागों तथा आजादी की लड़ाई में उनके योगदान की जानकारी मिली।

कांग्रेस संदेश पत्रिका को ऐसे और लेख छापने चाहिए जिससे हम लोगों को अपनी महान् पार्टी के गौरवपूर्ण इतिहास का पता लग सके। युवक कांग्रेस तथा पार्टी की दूसरी अग्रणी संस्थाओं के प्रशिक्षण शिविरों में भी इस तरह की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि हमलोग अपने आपको कांग्रेसी कहने में गर्व महसूस कर सकें।

टिकेन्द्र ठाकुर,
रायपुर

भड़काउ बयान

शिवसेना के मुखपत्र "सामना" में श्रीबाल ठाकरे की टिप्पणियों से हिंसा भड़केगी। राजनीतिक नेताओं द्वारा ऐसी उकसावाभरी टिप्पणियां करना बड़े शर्म की बात है। भारत एक जनतांत्रिक गणतंत्र है और यहां विविधता में एकता ही इस देश को दूसरे देशों की तुलना में विशिष्ट स्तर प्रदान करती है। "इस्लामी आतंकवाद" का सामना करने के लिए "हिन्दू आत्मघाती दस्ता" बनाने संबंधी शिव सेना नेता के भड़काउ बयान के खिलाफ न्यायपालिका द्वारा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि हर आदमी को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है, परन्तु वरिष्ठ नेताओं का संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। किसी भी धर्म के नाम पर आतंकवाद की कार्रवाई निन्दनीय है। ऐसा लगता है कि आत्मघाती हिन्दूदस्ता की बात कहकर बाल ठाकरे आतंकवाद को उचित ठहराना चाहते हैं। धर्म पर आधारित किसी भी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी से हमारे गणतांत्रिक जनतंत्र के लिए गंभीर वतरा ही पैदा होगा।

अशोक कुमार
महावीर इन्कलेव, नई दिल्ली

शिक्षाप्रद

कांग्रे संदेश पत्रिका पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक महत्व की पत्रिका बन गई है। इस पत्रिका के माध्यम से देश के सुदूरवर्ती इलाकों में रहनेवाले लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहती हैं। मई २००८ के अंक को पढ़ने से पंचायती राज के बारे में पूरी जानकारी मिली। इसके लिए इसके लेखक तथा सम्पादकीय टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस संदेश में ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से लेख छापे जाने चाहिए।

रमेश दूबे
इटारसी (म.प्र.)

अच्छा लेख

मैंने बाबू जगजीवन राम संम्बंधी लेख पढ़ा तथा यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि इस दलित मशीहा को अब भी काफी आदर-भाव से देखा जाता है। मुझें प्रधानमंत्री के शताब्दी समारोह में दिए गए भाषण से उनके विचारों के बारे में भी जानकारी मिली। इससे दलितों, गरीबों और किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान का मार्ग-निर्देश तथा प्रेरणा मिलेगी।

मैंने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का संदेश भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों से मूल्यवृद्धि रोकने के उचित उपाय करने तथा इस काम को अपनी जिम्मेवारी समझकर पूरा करने का आग्रह किया है। मैं आम आदमी के प्रति चिन्ता करने के लिए आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं।

ममता भूपेश
सदस्य, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दौसा (राजस्थान)

उनकी क्षतिपूर्ति मुश्किल!

यह हमारे लिए दुखद है कि वरिष्ठ गांधीवादी नेता तथा समाज सेविका सुश्री निर्मला देशपांडे का १ मई, १००८ को निधन हो गया।

जैसाकि संदेश में छपा है, दीदी नाम से लोकप्रिय सुश्री देशपांडे को पद्म विभूषण, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार तथा अनेक अन्य सम्मान मिल चुके थे, परन्तु अगली पीढ़ी उन्हें उनके गांधीवादी मूल्यों के प्रति समर्पण भाव के लिए ही याद करती रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने सही ही कहा है, "उनके निधन से जो रिक्ति पैदा हुई है, उसे भर पाना मुश्किल" है।

– प्रमोद कुमार शर्मा,
बागपत

सम्पादकीय

एक और कीर्तिमान

यूपीए की यह कोशिश कि प्रगति के फल हरेक को मिले, उसके अग्रणी (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों से परिलक्षित हो रही है। नरेगा की व्यापक व्यवस्था तथा किसानों की कर्ज माफी समावेशी विकास के प्रति यूपीए की प्रतिबद्धता का एक अंश मात्र है।

चाहे लक्ष्य प्राप्त करना हो अथवा गंतव्य पर पहुंचना हो "मील के पत्थर" (माईलस्टोन) का हमेशा एक ही अर्थ होता है।

परन्तु, पहले किसी निर्वाचित सरकार ने अपनी समावेशी राजनीति के लिए ऐसा लक्ष्य तय नहीं किया था जो भारतीय राजनीति के सभी वर्गों तथा क्षेत्रों का हित-साधन करनेवाला हो तथा एक निर्धारित समय सीमा में पूरा होनेवाला हो। इसने न सिर्फ अपने लिए लक्ष्य तय किया, बल्कि हर कदम पर अपने लक्ष्यों की पूर्ति का रिपोर्ट कार्ड भी आम जन के सामने पेश करने की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री के शब्दों मेंः "यूपीए सरकार की वार्षिक रिपोर्ट ने प्रशासन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता के लिए नया मानदंड कायम किया है।"

भारत के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की भावना का ख्याल रखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि यह जनादेश निम्नलिखित मकसदों के लिए थाः

- पंथनिरपेक्ष मूल्यों की पुनर्स्थापना
- उन देशव्यापी मुद्दों के समाधान के लिए जो उपेक्षित रहे हैं;
- खेती तथा खेती के उत्पादन से संबंधित मुद्दों को महत्व देने के लिए;
- चतुर्दिक आर्थिक विकास करने के लिए;
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान तथा उनमें फिर से जान डालने के लिए।

इससे भी बढ़कर इन मुद्दों के अलावा राष्ट्र के सर्वाधिक कमजोर तथा गरीब लोगों की जरूरतों का ख्याल करने के लिए।

यूपीए सरकार इन तथा अन्य समस्याओं के समाधान में लगन की भावना से जुटी हुई है। यह उपलब्धियों का एक गौरवपूर्ण कीर्तिमान है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम इस तरह से तय किए गए हैं ताकि आम आदमी का उत्थान हो सके और भारत का वैश्विक कद ऊंचा हो सके।

यूपीए द्वारा शुरु किए गए अग्रणी कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरिगा), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, भारत निर्माण, विस्तारित सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याहन भोजन, खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसके समावेशी विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के माध्यम हैं।

विकास एवं मूल्यवृद्धि

जिस गरिमापूर्ण ढंग से भारत के लोगों ने पेट्रोलियम पदार्थों की ताजा मूल्यवृद्धि को स्वीकार कर लिया उससे उनकी विचार संबंधी परिपक्वता तथा वैश्विक वास्तविकता के प्रति उनकी जागरुकता का ही पता चलता है।

कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यूपीए चेयरपर्सन के आह्वान पर तुरंत ध्यान दिया और स्थानीय करों में कटौती कर मूल्यवृद्धि के एक बड़े हिस्से को समायोजित कर लिया। यह यूपीए की आम आदमी के प्रति प्रतिबद्धता का ही एक प्रमाण है।

विश्व स्तर पर तेल, इस्पात तथा खाद्यान्न की कीमतों में भारी वृद्धि का हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। सरकार ने इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। यूपीए सरकार विकास की रफ्तार को कायम रखे हुए है। यूपीए सरकार ने उचित मूल्य स्थिरता कायम रखते हुए विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश की है। मुद्रास्फीति को काबू करने के काम को उचित प्राथमिकता दी गई। यूपीए सरकार ने २००४-०५ तथा २००५-०६ में मुद्रास्फीति की दर को घटाकर ३ प्रतिशत से थोड़े ऊपर तक ले आई जबकि २००३-०४ में यह दर ६ प्रतिशत थी। लेकिन, २००७ के बाद से मूल्य में वैश्विक स्तर पर वृद्धि से मुद्रास्फीति में पहले की गई उम्मीदों से भी ज्यादा वृद्धि हो गई। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वित्तीय उपाय करके मूल्य कम किया जाएगा। ऐये वित्तीय उपाय करने में सरकार लगी हुई है।

वार्षिक ८ से ६ प्रतिशत की दर से विकास करने के लक्ष्य से राष्ट्र को गरीबी, अज्ञानता तथा बीमारियों से मुक्ति पाने के उपाय करने में मदद मिलेगी। ये तीनों समस्याएं सदियों से हमारे लाखों देशवासियों के भाग्य में बदी थीं। यूपीए यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है कि विकास की प्रक्रिया सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से समावेशी हो। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, शिक्षा, स्वास्थ्य निगरानी, सिंचाई तथा कृषि अनुसंधान, बुनियादी ढांचा ग्रामीण ढांचा सहित का मकसद घोषित मकसद को पूरा करना है।

यूपीए की यह कोशिश कि प्रगति के फल हरेक को मिले, उसके अग्रणी (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों से परिलक्षित हो रही है। नरेगा की व्यापक व्यवस्था तथा किसानों की कर्ज माफी समावेशी विकास के प्रति यूपीए की प्रतिबद्धता का एक अंश मात्र है।

प्रशासन में पारदर्शिता

इससे पहले ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसने यूपीए से ज्यादा पारदर्शिता दिखाई हो। यूपीए सरकार ने प्रशासन तथा न्याय प्रणाली में बड़े-बड़े सुधार शुरु किए हैं। सूचना के अधिकार तथा परियोजनाओं में ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र तथा नागरिक अधिकारिता के मामलों में भारी बदलाव आ गया है।

भावी लक्ष्य

कांग्रेस को अब अपनी सरकार के पांचवें साल में यूपीए की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी देने की तैयारी करने की जरूरत है। पार्टी संगठन को अपनी उपलब्धियों का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए अवश्य तैयारी करने की जरूरत है ताकि प्रशासन के सभी क्षेत्रों में यूपीए की भारी सफलता का हम लाभ उठा सकें। ❖

जनादेश का अनुपालन...

यूपीए सरकार के चार साल पूरे करने पर यूपीए चेयरपर्सन तथा कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण

प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी, यूपीए के सहयोगियो, मंत्रीगण, संसद सदस्यगण और साथियों,

चार साल पहले देश-वासियों ने हमें जनादेश दिया था।

यह जनादेश- हमारे समाज के उन सेकुलर मूल्यों को फिर से स्थापित करने के लिए था, जिन्हें समाप्त किया जा रहा था।

यह जनादेश- कृषि और उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में विकास की रफतार तेज करने के लिए था, जिनकी उपेक्षा हो रही थी।

यह जनादेश- समग्र आर्थिक विकास के लिए था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों को फिर से जीवंत बनाने के लिए था। यह सभी के, खास तौर से उनके सशक्तिकरण के लिए था, जो सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा कमजोर हैं।

हम सबने इसी पवित्र वादे का सम्मान करने और उसे पूरा करने के लिए यह गठबंधन और यूपीए सरकार बनायी।

प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह जी ने अभी विस्तार से हमें सरकार के कार्यक्रमों, सफलताओं और चिंताओं के बारे में बताया है। इसमें काफी कुछ ऐसा है, जिस पर हम गर्व कर सकते है। आज पीछे मुड़कर देखने पर, हमें यह संतोष है, कि देश से हमने जो वादे किए थे, उनमें से बहुत से पूरे कर दिए हैं।

यूपीए सरकार के चार साल पूरे होने पर अभी जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसमें हमारे कार्यो का विस्तृत ब्योरा है। इसमें कोई भी दावा गलत या बढ़ा-चढ़ाकर नहीं पेश किया गया है। यह प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के अड़तालीस महीने के कार्य-काल का सच्चा लेखा-जोखा है। यह पूरी तरह से पारदर्शी और एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे कोई भी जांच सकता है। हम सभी जानते हैं कि स्वभाव से ही हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि वे नहीं, बल्कि उनके कार्य बोलें। उनके नेतृत्व की विशेषताएं सबकी समझ में थोड़ा मुश्किल से आती हैं, लेकिन वक्त साबित कर देता है कि वह नेतृत्व कितना प्रभावशाली है। उन्होंने सरकार को एक दृष्टि और दिशा दी है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से सरकार की उपलब्धियों के लिए, देश को सामाजिक और आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए उन्हें बधाई देती हूं।

हम जो यह कार्यक्रम हर साल करते हैं, वह केवल एक रस्म नहीं है। हम सिर्फ एक साल-गिरह नहीं मनाते हैं। यह एक ऐसा अवसर है, जब हम अपने देश के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और एक सार्थक शासन देने के लिए अपना संकल्प दोहराते हैं।

इसमें कोई भी दावा गलत या बढ़ा-चढ़ाकर नहीं पेश किया गया है। यह प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के अड़तालीस महीने के कार्य-काल का सच्चा लेखा-जोखा है। यह पूरी तरह से पारदर्शी और एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे कोई भी जांच सकता है।

हम जो यह कार्यक्रम हर साल करते हैं, वह केवल एक रस्म नहीं है। हम सिर्फ एक साल-गिरह नहीं मनाते हैं। यह एक ऐसा अवसर है, जब हम अपने देश के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और एक सार्थक शासन देने के लिए अपना संकल्प दोहराते हैं।

यह सही है, कि हमारे सभी सहयोगी और समर्थक दलों की अपनी एक विशेष स्थिति और दृष्टि-कोण है, फिर भी हम जनता की इच्छाओं के मुताबिक और मौजूदा चुनौतियों के जवाब में एक साथ खड़े है।

अब यूपीए सरकार के कार्य-काल का आखिरी साल शुरू हो रहा है, निश्चय ही अगला साल निर्णायक होगा। हमें अब अपने साझा कार्यक्रम के उन वादों को पूरा करना है जो अभी बाकी हैं। हमारे अनेक कार्यक्रमों का अच्छा प्रभाव लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। हमें उनका समाज के सभी वर्गों के बीच सही तरीके से प्रचार-प्रसार करना है।

आज जब हम अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर रहे हैं, अपने अच्छे कार्यों का जिक्र कर रहे है, तो उसी समय हमें भविष्य की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का भी एहसास है। लेकिन मुझे यकीन है, कि हम एक साथ खड़े होकर, संगठित रहकर उनका कामयाबी के साथ मुकाबला कर सकते हैं।

अंत में मै एक बार फिर प्रधानमंत्री जी और यूपीए के अपने सभीं सहयोगियों को धन्यवाद देती हूं। सबने निष्ठा और सच्चे मन से, सिर्फ अपनी पार्टी के हितों का ख्याल न करके, सामूहिक लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर, गठबंधन को शक्ति प्रदान की है। मुझे विश्वास है, कि आनेवाले महीनों में भी हम एक टीम की तरह काम करेंगे और अपने लिए फिर से देश-वासियों की एक नयी सद्भावना अर्जित करेंगे। जय हिन्द। ❖

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के सिद्धांत एवं लक्ष्य

22 मई, 2008 को संप्रग सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के भाषण का मूलपाठ इस प्रकार है।

"चार वर्ष पहले भारत की जनता ने अपने लिए एक नयी राह तैयार की। वह एक ऐसी सरकार चाहती थी जो भारत की जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। जनता ने ऐसी राजनीति और अर्थनीति की आकांक्षा की जिसके दायरे में सभी आते हैं। वे एक ऐसी सरकार चाहते थे कि क्षेत्र, भाषा, जाति, समुदाय या पंथ के परे प्रत्येक भारतीय कह सके कि यह "हमारी सरकार" है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसे मूल्यों का हमेशा ही समर्थन एवं प्रतिनिधित्व किया है। श्रीमती सोनिया गांधी के प्रेरणादायी नेतृत्व के अंतर्गत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ऐसे ही मूल्यों की आधारशिला पर खड़ा है। इन मूल्यों ने ही हमें हमारे लोगों का विश्वास दिलाया है। हमने एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम अपनाया जिसने हमारी सरकार के विचार एवं कार्य का मार्गदर्शन किया। पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया है और जब भी संभव हुआ, प्रयासों को तेज किया गया।

मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश के शासन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी सरकार ने शासन के दौरान जो करने का प्रयास किया उसका रिकार्ड पेश करने के लिए वह हर साल जन रिपोर्ट लेकर हाजिर हुई है। संप्रग सरकार की इस वार्षिक रिपोर्ट ने शासन में जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि संप्रग सरकार राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जनता को दिए गए वचनों को पूरा करने में अभी तक सफल रही है।

फ्लैगशिप कार्यक्रम, जो हमने शुरु किए जैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, भारत निर्माण, विस्तृत सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आधार पर हमारी सरकार ने "समग्र विकास की संरचना" शुरु की।

वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों की आजीविका एवं भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए हमने कानून बनाया है। यह योजना पिछड़े जिलों के त्वरित विकास पर विशेष फोकस के साथ और क्षेत्रीय संतुलित विकास को सुनिश्चित भी करता है, जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, उन क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान एवं महत्व दिया जा रहा है। हम कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत और आर्थिक सुरक्षा और महिला एवं बालिका शिशु के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रहे हैं। हमने बाल कुपोषण एवं बाल अधिकारों की चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ प्रयास किए हैं। आई.सी.डी.एस. और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का काफी विस्तार किया गया है।

हमारी सरकार ने कृषि को नया जीवन देने किसानों के सशक्तिकरण और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी है।

. . .संप्रग सरकार की इस वार्षिक रिपोर्ट ने शासन में जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि संप्रग सरकार राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जनता को दिए गए वचनों को पूरा करने में अभी तक सफल रही है।

१९६० के दशक के मध्य से कृषि की एक दशक लंबी उपेक्षा को पलटने के लिए इस रिपोर्ट में सूचीबद्ध कई कदम उठाये गये हैं। हमने अपने किसानों के लिए व्यापार की शर्तों में सुधार किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है खाद्यान्न के लिए देय न्यूनतम समर्थन मूल्यों को बढ़ाना। हमने सिंचाई, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं में निवेश को बढ़ाया है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए २५,००० करोड़ रूपये आबंटन के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरु की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के साथ

ये कदम और इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में वित्तमंत्री द्वारा घोषित ६०,००० करोड़ रूपये के किसान ऋण राहत पैकेज हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के रूपांतरण में मदद करेंगे।

हमारी सरकार ने उचित कीमत स्थिरता को बनाये रखते हुए विकास की गति को तेज करने के लिए दृढ़ प्रयास किए हैं। मुद्रास्फीति का नियंत्रण प्राथमिक चिंता का विषय रहा है। संप्रग सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि २००३-२००४ में ६ प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर को २००४-०५ और २००५-०६ वर्षों में घटकर ३ प्रतिशत से थोड़ा ऊपर तक लाया जाय। वर्ष २००७ से ही विश्व बाजार में जिन्सों की कीमतों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जाती रही है। इनमें खासतौर से तेल और खाद्यान्न की कीमतें शामिल हैं। इसकी वजह से हमारे देश में भी कीमतों में वृद्धि कर रूझान रहा।

अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों, इस्पात की कीमत और खाद्य फसलों की कीमत में तेज उछाल ने हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हमारी सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगायी गयी है, सस्ते आयात को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क घटाये गये हैं, राजकोषीय एवं मौद्रिक पहलें की गई हैं और जहां आवश्यकता है, वायदा बाजार एवं जमाखोरी को रोकने के लिए प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। जहां आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष के उपायों का कीमत स्तर पर हितकारी प्रभाव होगा, एक सामान्य मानसून और मुद्रास्फीति में हाल की वृद्धि को पलटने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय को सार्वजनिक मान्यता भी अनुमानों की अवस्था में सुधार लाने में मदद करेगा। अभी तक रबी फसल की रिपोर्ट अच्छी है और एक अच्छे मानसून की भविष्यवाणी हमें आशा एवं विश्वास देती है कि अभी तक हमारे द्वारा उठाये गये कदम ८ से १० सप्ताहों के समय में कम मुद्रास्फीति वाले काल में लौटने में हमें सक्षम बनाएंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर है और ८-६ प्रतिशत वार्षिक विकास दर कायम रखी जा सकती है। इस दर पर हम, हमारे देश को भयानक गरीबी, उपेक्षा और बीमारी से जो सदियों से हमारे लाखों देशवासियों की किस्मत रही है, छुटकारा दिला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम उत्पादन बढ़ाने और अपने लोगों की बढ़ती मांगों और अधिक रोजगार सृजन करने में सक्षम होंगे। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारी विकास प्रक्रिया सामाजिक एवं क्षेत्रीय रूप से समेकित हो। हमें इस बात का गर्व है कि हम सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य की देखभाल में, सिंचाई में, कृषि अनुसंधान में, और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं समेत बुनियादी सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने में सफल रहे हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का शिक्षा पर विशेष ध्यान है। भारत युवा लोगों का देश है। मैं आशा करता हूं कि सभी स्तरों पर शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो पहल की हैं वे हमारे लोगों, खासतौर पर युवा लोगों, की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। हमने शिक्षा की पहुंच के विस्तार एवं उत्कृष्टता के उन्नयन के जुड़वा लक्ष्यों के साथ शिक्षा में निवेश बढ़ा दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य कल्याण, शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इस रिपोर्ट में इन सबकी विस्तृत चर्चा की गयी है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस वर्ष के दौरान अपने देश के सभी ग्रामीण जिलों को शामिल करके हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का सार्वभौमिक फैलाव कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्रामीण भारत में अत्यधिक गरीबी को कम करने में प्रमुख योगदान देगा। मैं सभी राज्य सरकारों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए अनुरोध करता हूं।

संप्रग सरकार ने हमारी विकास प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समेकित और क्षेत्रीय रूप से संतुलित बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है और मिलता रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में विकास के लाभों को पहुंचाना हमारे सामने आंतरिक सुरक्षा की कुछ चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की कुंजी भी है। हम उत्तरदायित्व, विकेन्द्रीकरण और न्यायसंगत विकास के उन्नयन के साधन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हैं। आतंकवादी एवं अन्य विघटनकारी तत्वों ने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर परेशानी खड़ी करना जारी रखा है। उनका लक्ष्य हमारी जनता के बीच नफरत एवं अविश्वास फैलाना है। भारत की जनता हमारी महान विविधताओं में एकजुट होकर इन तत्वों को कभी भी सफल नहीं होने देगी। सप्रंग सरकार ने संपूर्ण सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने के लिए कड़े उपाय किए हैं और हमारे पवित्र गणतंत्र की अखंडता एवं एकता को किसी खतरे के खिलाफ यह सरकार हमेशा सतर्क रहेगी। ऐसी ताकतों के खिलाफ जहां भी आवश्यकता होगी हम कठोर एवं कड़ी कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे और ऐसे खतरों का सामना करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे।

हमारी सरकार ने इन पिछले चार वर्षों में अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया भारत एवं भारत के उद्यमी लोगों की तरफ सम्मान एवं प्रशंसा से देखती है। एक ऐसे माहौल का निर्माण करके, जिसमें भारतीय लोगों की रचनात्मक एवं मेधा को मुक्त अभिव्यक्ति मिली है, हमने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया है।

हमारे देश की रूपरेखा और मजबूत हुई है और परिणामस्वरूप इसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में सुधार लाने में भी योगदान दिया है। इसने हमें अपने पड़ोसियों तक पहुंचने और दक्षिण एशिया, दक्षिणपूर्व एशिया, हिन्द महासागर क्षेत्र और अफ्रीका के देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में भी समर्थ बनाया है। हम अपने एकदम पड़ोस में प्रजातंत्र की नई लहर का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। ❖

सर्वनिहित विकास की संरचना

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने जनता की जानकारी के लिए बनाई गई यह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करके शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के नये मानक स्थापित किए हैं।

पिछले चार सालों के दौरान यूपीए सरकार हर साल राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नवीनतम स्थिति से जनता को अवगत कराती रही है। इस वर्ष की रिपोर्ट को मिलाकर अब तक पेश की गई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि यूपीए सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये अपने वायदों को अब तक काफी हद तक पूरा करने में कामयाब रही है।

पिछले तीन सालों के दौरान की गई पहल, खासकर भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, विस्तारित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम सहित पुनरीक्षित सर्व शिक्षा अभियान जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने अपने कार्यकाल के इन चार सालों के दौरान "सर्वनिहित विकास का एक ढांचा" तैयार किया है। इस साल शुरु की गई ११वीं पंचवर्षीय योजना इसी ढांचे पर आधारित है।

११वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी विकास प्रक्रिया शुरु करना है जो हमारे लोगों, विशेष कर गरीबों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार ला सके। इस योजना में क्षेत्रीय स्तर पर अधिक संतुलित विकास पर भी जोर दिया गया है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने कृषि में नई जान फूंकने, हमारे किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा की गई कई पहलों को दर्शाया गया है जिनका उद्देश्य वर्ष १९९६ से वर्ष २००४ की अवधि के दौरान उपेक्षित रह गये कृषि क्षेत्र को विकास की पटरी पर वापिस लाना है। हमने कृषि व्यापार के क्षेत्र में सुधार किया है, खासकर खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके तथा सिंचाई, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाकर, और ११वीं पंचवर्षीय योजना के लिए २५,००० करोड़ रूपये के आबंटन से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरु की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय किसान नीति के साथ-साथ हमारी ये पहलें कृषि अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगी। मुझे पूरा यकीन है कि हम इससे मंहगाई की दर को मामूली स्तर पर बनाए रखने में भी सफल होंगे।

हमारी सरकार ने उचित मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए दृढ़ प्रयास किए हैं। मंहगाई पर नियंत्रण प्राथमिकता का विषय रहा है। सरकार ने मुद्रास्फीति की दर, जो वर्ष २००३-०४ में लगभग ६ प्रतिशत थी, वर्ष २००४-०५ और २००५-०६ में लगभग ३ प्रतिशत के आसपास बनाये रखा। वर्ष २००७ से कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी गई है वह पूरी तरह से दुनिया भर में उपयोगी वस्तुओं की कीमतों, खासकर तेल की कीमतों, में भारी वृद्धि के कारण हुई है। तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और धातुओं - खासकर इस्पात तथा खाद्यान्नों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण लागू किया गया है, आयात को सस्ता बनाने के लिए सीमा शुल्क को कम किया गया है, प्राधिकारियों द्वारा राजकोषीय और मौद्रिक नीति संबंधी पहल की गई है और जहां जरूरी समझा गया है, अटकलबाजियों और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं।

११वीं पंचवर्षीय योजना के शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। भारत में युवाओं की तादाद सर्वाधिक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो पहल की है उनसे हमारे युवा वर्ग की रचनात्मक क्षमता उभरकर सामने आएगी। हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो निवेश बढ़ाया है, उसके दो उद्देश्य हैं - शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाए जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल, शहरी विकास और अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के संबंध में भी महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इन सबके बारे में इस रिपोर्ट में विस्तृत उल्लेख किया गया है।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को देश भर के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण भारत में घोर गरीबी की विभीषिका को कम करने में बड़ा योगदान करेगा। राज्य सरकारों से मेरा आग्रह है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का समुचित और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

यूपीए सरकार ने समाज के सभी तबकों को विकास प्रक्रिया से जोड़ने और विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए कड़ी मेहनत की है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और दूसरे पिछड़े क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में भी काफी काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त होकर उभरी है और दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। इसके कारण हम अपने पड़ोसी देशों से भी संबंधों को बेहतर बनाने और दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र और अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में भी सफल हुए हैं।

हमारी विदेश नीति इस सोच से प्रेरित रही है कि हम एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार करें जो हमारे क्षेत्र में शांति और स्थायित्व लाने के अनुकूल हो और जिसमें भारत का तेजी से आर्थिक विकास हो तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के हित सुरक्षित रहें। हमने अपने सभी पड़ोसी देशों, सभी बड़ी ताकतों और विकासशील विश्व तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अपने सहयोगी देशों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है।

भारत की छवि आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसे स्थायी, उदार, विविधतापूर्ण और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है जो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने की क्षमता और काबलियत रखता है।

मैं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता को प्रस्तुत इस वार्षिक रिपोर्ट को सभी लोग पढ़ेंगे और हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को बेहतरी से समझेंगे। ❖

जीवन सम्बंधी वादों को पूरा करना

यूपीए सरकार की 2004-2008 की जनता के नाम रिपोर्ट

2.1 स्वास्थ्य

यूपीए सरकार ने कई ऐसी पहलें की हैं जिनसे लोगों को, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, गरीब जनता, महिलाओं एवं बच्चों को सही मायनों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो। इन प्रयासों से स्पष्ट और उल्लेखनीय अंतर दिखने लगे हैं। वर्ष २००३-०४ में स्वास्थ्य आयोजना का आकार ६,६८३ करोड़ रूपसे से बढ़कर सन् २००८-०६ में १६,५३४ करोड़ रूपये हो गया है।

2.1.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से बाह्य रोगियों की देखभाल, संस्थागत प्रसव और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

2.1.3 एड्स नियंत्रण एवं देखभाल

- यूपीए सरकार में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को प्रधान मंत्री के स्तर से नेतृत्व प्रदान किया गया है। पिछले चार वर्षों में इस रोग के फैलाव में आंशिक गिरावट देखने में आई है तथा रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी थमी है।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रोकथाम, सलाह, जांच एवं उपचार सेवओं का व्यापक विस्तार किया गया है। पिछले ४ वर्षों में एड्स संबंधी सलाह और जांच से लाभान्वित लोगों की संख्या छह गुना बढ़कर ६० लाख हो गई है। रोकथाम एवं उपचार सेवाओं में भी इसी प्रकार का विस्तार हुआ है।

2.1.4 प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

- यूपीए सरकार ने प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर ८५० बिस्तरों वाले अस्पताल के ६ नए चिकित्सा संस्थान और १३ मौजूदा संस्थानों के उन्नयन को अनुमोदित किया है ताकि सेवा-वंचित राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा प्राप्त हो सके। पहले से कार्यरत ७ चिकित्सा संस्थानों में निर्माण कार्य शुरु हो गया है तथा इस वर्ष भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर एवं ऋषिकेश में ६ नए चिकित्सा संस्थानों में निर्माण कार्य शुरु हो जाएगा।

2.1.5 असंगठित क्षेत्र के गरीबों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

- यूपीए सरकार ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ३०,००० रूपये की परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा देने की शुरुआत १ अप्रैल, २००८ से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्यों से कर दी है।

2.1.6 सर्वव्यापी ग्रामीण स्वच्छता

- यूपीए सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लाभार्थी ग्रामीण परिवारों की संख्या दोगुनी कर दी है। इस अभियान के तहत लोगों की बढ़ी भागीदारी के बूते आधे से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब शौचालय सुविधा उपलब्ध करने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान को तेज कर दिया गया है।

2.1.7 सड़क दुर्घटना से हुए आघात के लिए चिकित्सा केन्द्र

- यूपीए सरकार ने सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के अविलंब उपचार के उद्देश्य से स्वर्णिम चतुर्भुज एवं पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा केन्द्रों के उन्नयन को अनुमोदित किया है।

२.१.८ सस्ती जीवनरक्षक दवाइयां

- यूपीए सरकार हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि. एवं बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. के पुनरूद्धार के लिए व्यापक योजना लागू कर रही है ताकि इन सार्वजनिक दवा निर्माता कंपनियों के माध्यम से अनिवार्य दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकें।

2.1.9 एकीकृत बाल विकास योजना का सर्वव्यापीकरण एवं सशक्तिकरण

- यूपीए सरकार ने ३.२ लाख नई आंगनवाड़ियों का अनुमोदन किया है और ११वीं योजना में हरेक बस्ती में एक आंगनवाड़ी सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। पूरक पोषक आहार की आपूर्ति के लिए प्रति लाभार्थी वित्तीय प्रावधान के स्तर को दुगुना कर दिया गया है ताकि वांछित पोषण सुनिश्चित हो सके।

2.1.10 आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी पर पूरा ध्यान

- यूपीए सरकार ने चिकित्सा की इन पद्धतियों पर अभूतपूर्व बल दिया है। ११वीं योजना में इनका बजट ५ गुना से अधिक बढ़ाकर ४,००० करोड़ रूपये कर दिया गया। ५,००० से अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में इन पद्धतियों के तहत सेवा उपलब्ध कराई गई है। ४,००० चिकित्सक भी नियुक्त किए गए हैं।

2.2 शिक्षा

समाज के हर वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों स्तरों पर प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत क्रियान्वयन जारी है। इससे सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूपीए सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष २००३-०४ में शिक्षा पर ७,०२४ करोड़ रूपये आयोजना आबंटन बढ़कर वर्ष २००८-०६ में ३४,४०० करोड़ रूपये हो गया है। पंचवर्षीय योजना के तहत ५ गुना से अधिक बढ़त के साथ यह राशि ११वीं योजना में २,७५,००० करोड़ रूपये हो गई है।

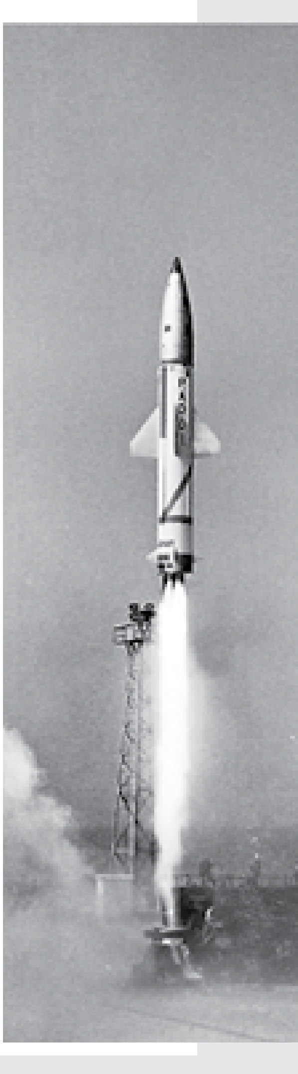

2.2.2 सभी को स्कूली शिक्षा

- १,७५४ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए १,८२,००० बालिकाएं इन विद्यालयों में दाखिला ले चुकी हैं। इससे शिक्षा में लड़के-लड़कियों के बीच का अंतर घटा है। ८६ प्रतिशत से अधिक बस्तियों को एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और ८५ प्रतिशत को उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा दी गई है। इस वर्ष देश भर में ६,००० उच्च कोटि के आदर्श विद्यालय आरंभ किए जाएंगे ताकि अन्य विद्यालयों के लिए उत्कृष्टता का एक मानक स्थापित हो सके।
- यूपीए सरकार ने प्रति वर्ष माध्यमिक विद्यालयों के एक लाख बच्चों के लिए एक आय-सह-प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। प्रत्येक को सालाना ६,००० रूपये दिए जाएंगे।
- पिछले ४ वर्षों में १.५८ लाख ग्रामीण स्कूलों के लिए सुरक्षित पेयजल का प्रावधान किया गया है। यूपीए सरकार ने अगले चार

वर्षों में जल संकटग्रस्त बस्तियों के प्रत्येक स्कूल में सुरक्षित पेयजल की इकाइयां लगाने की घोषणा की है।

2.2.3 उच्च शिक्षा सुलभ करना

- यूपीए सरकार ने शिलांग में एक आईआईएम तथा मोहाली, पुणे एवं कोलकाता में तीन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है। कांचीपुरम में अभिकल्प एवं प्रबंधन हेतु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीडीएम) की स्थापना की गई है।
- ११वीं पंचवर्षीय योजना में उचच शिक्षा पर भारी निवेश किया जाएगा। ३० नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ३७० नए महाविद्यालय, ८ नए आईआईटी, २० भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ७ नए आइआईएम, और २ नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुलेंगे। इनमें से १६ केन्द्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान में तीन आईआईटी, भोपाल एवं तिरूवनंतपुरम में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तथा भोपाल एवं विजयवाड़ा में दो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इसी वर्ष खुलेंगे।
- गीगाबिट ब्रॉडबैंड सुविधा देने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जाएगी ताकि देशभर के सभी उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परस्पर जुड़े रहें और संसाधनों एवं अनुसंधान में परस्पर सहयोग कर सकें।
- यूपीए सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि बिना किसी ऋणाधार छात्र-छात्रओं को ७.५ लाख रूपये का ऋण प्रदान करें। साथ ही निरंतर निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। इससे छात्र ऋण लाभार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ गई हैं।
- राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येयतावृत्ति योजना की शुरुआत की गई है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अकादमिक संस्थानों में चयन तथा पीएचडी अध्ययन के लिए तैयारी कर सकें।
- दो लाख रूपये तक सालाना आमदनी वाले परिवार से आए आईआईएम छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति की पात्रता दी गई है।

2.2.4 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

- यूपीए सरकार ने एक राष्ट्रीय कौशल मिशन का प्रारूप तैयार किया है ताकि युवा पीढ़ी को रोजगार सुनिश्चित हो तथा अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कुशल कामगार के अभाव को दूर किया जा सके। ११वीं योजना में इसके लिए ३१,००० करोड़ रूपये का व्यय लक्षित है।

2.3 बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के गठन, बच्चों के लिए अनुकूल कानून पारित करने तथा बाल विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत से यूपीए सरकार ने बाल विकास के लिए ठोस पहल की है। बच्चों से संबंधित योजनाओं के लिए ३३,००० करोड़ रूपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।

2.3.1 बच्चों के लिए अनुकूल कानून

- यूपीए सरकार द्वारा पेश विधेयक बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम, २००६ बन गया है। इसके तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है। इस कानून के अंतर्गत बच्चों के प्रति अपराध और बाल अधिकार हनन के मामलों की सुनवाई के लिए राज्य आयोगों एवं बाल न्यायालयों की स्थापना का आज्ञापक प्रावधान है।

2.3.2 बच्चों को सुनिश्चित शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य

- यूपीए सरकार ने बच्चों की सुनिश्चित शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के माध्यम से हरेक बस्ती में आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सुरक्षित पेयजल और स्कूल का प्रावधान किया गया है। कामकाजी माताओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुग्रह योजना शुरु की गई है जिसके तहत २८,००० शिशुग्रह में ७ लाख बच्चों की देखभाल होती है।

सामाजिक समावेश में वृद्धि

3.1 अल्पसंख्यकों के सामाजिक समावेश का एजेंडा

यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों के बेहतर सामाजिक समावेश के लिए व्यापक एजेंडे को अपनाया है तथा उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से अल्पसंख्यक मामलों पर पूरा ध्यान दिया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना की गई है और इसके लिए बजट में त्वरित वृद्धि की गयी है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट दुगुना कर दिया गया है। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए विधेयक पेश किया है।

3.1.3 शिक्षा के बेहतर अवसर

- यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग का गठन किया है। अब अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को अपनी पसंद के किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंधन संबंधी संवैधानिक अधिकार ढंग से लागू हों। यूपीए सरकार ने मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष एक कार्यक्रम शुरु किए जाने की घोषणा की है।

3.1.4 हज यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था

- यूपीए सरकार ने हज समिति यात्रा कोटा ७२,००० से बढ़ाकर १,१०,००० कर दिया है।

3.1.5 उर्दू चैनल

- यूपीए सरकार ने २४ घंटे का एक उर्दू चैनल शुरु किया है ताकि उर्दू बोलने वाले लोगों की भाषाई आकांक्षाएं पूरी हो सकें तथा उर्दू की संपन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बचाया और बढ़ाया जा सके।

3.2 महिला सशक्तिकरण

यूपीए सरकार ने एक स्वतंत्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन कर महिला संबंधी मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया है। महिलाओं को पूर्ण कानूनी समानता देने के लिए अनेक पहल की गई है। इससे सबके द्वारा जीवन के हर पहलू में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

3.2.1 कानून

- यूपीए सरकार की पहल पर महिला घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, २००५ लागू किया गया है जिसके तहत किसी भी प्रकार की पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को अधिक कारगर सुरक्षा मिली है और उन्हें ऐसी हिंसा से बचने के गैर फौजदारी उपाय मिले हैं। यूपीए सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५५ में संशोधन के माध्यम से सहदायिकी संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों के समान उत्तराधिकार देने की पहल की है।

3.2.2 वित्त व्यवस्था पर अधिक ध्यान

- यूपीए सरकार ने महिला समानता को ध्यान में रखकर बजट पेश करने का चलन शुरु किया है ताकि महिला कल्याण की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। १०० प्रतिशत महिला-विशेष कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान साल-दर-साल बढ़ रहा है और इस वर्ष यह ११,४६० करोड़ रूपये है।
- ११वीं योजना के तहत यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में न्यूनतम ३३ प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं एवं

लड़कियां हों।

3.2.3 महिला आरक्षण

- विधायिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण हेतु एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए यूपीए सरकार ने सभी विपक्षी दलों समेत यूपीए के घटक दलों के साथ भी बैठकों का आयोजन किया। महिला समूहों एवं अन्य भागीदारों के साथ भी बैठकें हुईं। सरकार ने अब संसद में यह विधेयक पेश किया।

3.2.4 बालिका शिक्षा

- २,१८० आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा उनमें विद्यालयीन शिक्षा से वंचित १,८२,००० बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है।

3.2.5 सेना में महिला अधिकारी

- लघु अवधि के लिए सैन्य सेवा में कार्यरत अधिकारियों समेत सभी अधिकारी अब क्रमशः २,६ और १३ वर्षों की मान्य सेवा के बाद कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट के महत्वपूर्ण पद ग्रहण कर सकते हैं। अब लघु अवधि के लिए सैन्य सेवा में कार्यरत अधिकारियों की सेवा अवधि को १० वर्ष से बढ़ाकर १४ वर्ष की जा सकती है। इस प्रकार महिला अधिकारियों की उनके समतुल्य पुरुष अधिकारियों से बराबरी सुनिश्चित की गई है।

3.3 कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण एवं विकास

यूपीए सरकार ने प्रगतिशील विधेयकों, सरकारी सेवा में बेहतर भागीदारी, व्यापक कार्यक्रमों के आरंभ एवं बेहतर निवेश के माध्यम से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण एवं विकास पर बहुत बल दिया है।

3.3.1 सकारात्मक कार्य

- यूपीए सरकार ने पूर्व के रिक्त आरक्षित पदों को भरने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व विशेष भर्ती अभियान चलाया और इसके माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की प्रत्यक्ष नियुक्ति एवं पदोन्नति कर ५३,००० रिक्त पदों को भरा।

3.3.2 शिक्षा

- यूपीए सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के प्रावधान का विस्तार किया है।

3.3.3 मैला ढोने वालों का पुनर्वास

- यूपीए सरकार ने मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए एक नई स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उन्हें वैकल्पिक रोजगार अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है तथा स्वरोजगार के उपक्रम में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

3.3.4 अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों का वनों पर अधिकार

- यूपीए सरकार की पहल पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पा. रंपरिक वनवासी (वन्य अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, २००६ कानून बना तथा इसे इस वर्ष अधिसूचित भी कर दिया ताकि ऐतिहासिक तौर पर आदिवासी एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकार में मौजूद जमीनों पर उन्हें अधिकार प्रदान किया जा सके, जो वस्तुतः उनके अधिकार को दर्ज नहीं किए जाने की ऐतिहासिक भूल को सुधारना होगा। वन्य भूमि पर अधिकार के अतिरिक्त उन्हें लघु वनोपज एवं सामुदायिक संपदाओं पर भी अधिकार दिए गए हैं।

3.3.5 आदिम जनजातियों का कल्याण एवं विकास

- यूपीए सरकार ने ४ लाख आदिम जनजाति परिवारों को जनश्री बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा दी है। प्रत्येक आदिम जनजाति के लिए एक दीर्घकालिक संरक्षण-सह-विकास योजना बनाई गई है और ११वीं योजना में इसके लिए ६७० करोड़ रूपये की राशि निर्धारित है। यूपीए सरकार ने २,३९८ वन्य ग्रामों के विकास के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए ४५६ करोड़ रूपये की सहायता राशि दी गई है।

3.3.7 अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के खेतों का विकास

- यूपीए सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के खेतों के विकास और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई कार्यक्रमों और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के माध्यम से बड़ा प्रयास किया है।

3.3.8 वित्त विकास निगम

- यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय वित्त विकास निगमों के माध्यम से अनुस. ूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों और सफाई कर्मचारियों के लिए पिछले ४ वर्षों में क्रमशः १,७३,०००, १,४५,००० तथा ६७,००० व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी है। इस अवधि में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम ने ५०,००० लोगों को आय बढ़ाने की गतिविधि में सहायता प्रदान की है। सरकार इन निगमों की शेयरधारिता बढ़ा रही है ताकि उनकी गतिविधियों का और विस्तार हो सके।

3.4 विकास में विकलांग व्यक्तियों का समावेश

यूपीए सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाई है तथा उस पर प्रभावी कार्यवाही में जुटी है। इस उद्देश्य से सरकारी रोजगार, निजी रोजगार के लिए प्रेरक योजनाओं और विकास एवं कल्याण के अन्य उपाय किए जा रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए १६ लोक सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप लोक सेवाओं

- अंधेपन, कमजोर दृष्टि, बहरेपन, चलने में अक्षमता या मस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त लोगों की बढ़ती नियुक्ति देखी जा सकती है।

3.4.2 कल्याण एवं विकास के उपाय

- आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना का विस्तार किया गया है। अब अधिक आय समूह के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही, विकलांगों हेतु मोटर युक्त तिपहिया, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आदि योजना में शामिल किए गए हैं।

3.5 स्वतंत्रता सेनानी

- यूपीए सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनसाथी के लिए पेंशन की रकम दुगुनी, १०,००० रूपये कर दी है। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की अविवाहित एवं बेरोजगार लड़कियों के लिए मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर सबसे बड़ी लड़की के लिए ६०० रूपये तथा छोटी लड़कियों के लिए ३५० रूपये और सभी लड़कियों के लिए कुल मिलाकर १,५०० रूपये तक कर दी गई है।

3.6 वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल

- वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन, अधिक बचत तथा अधिक आय की सुविधा, वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा तथा एक विशेष विधेयक पेश कर यूपीए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच का विस्तार किया है। यह विधेयक लागू होने पर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी।

३.६.२ यूपीए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस वर्ष चालू होने वाले एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत २ राष्ट्रीय वृद्धावस्था संस्थान, ८ क्षेत्रीय केन्द्र और ११वीं योजना में प्रत्येक राज्य के एक चिकित्सा महाविद्यालय या तृतीयक स्तर के अस्पताल में वयोवृद्ध चिकित्सा देखभाल के विशेष विभाग खोले जाएंगे।

3.7 सेवानिवृत्त एवं सेवारत सैनयकर्मियों का कल्याण

- यूपीए सरकार ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी विभाग की स्थापना की है ताकि सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के पुनर्वास पर पूरा ध्यान दिया जा सके।
- उद्योग संघों के सहयोग से सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को नौकरियां देने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया ताकि सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को आर्थिक रूप से लाभदायी रोजगार मिल सके। सन् २००७ में ४५,००० से अधिक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को पुनः रोजगार सुनिश्चित किया जा सका।

3.8 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कल्याण

- आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था बीमा योजना से यूपीए सरकार ने एक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने का काम शुरु कर दिया है।

3.8.1 असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग

सलाह एवं निगरानी संगठन के रूप में असंगठित क्षेत्र में रोजगार हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग सरकार को नियमित रूप से रिपोर्ट दे रहा है। इसके सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

3.8.2 सामाजिक सुरक्षा के प्रयास

- यूपीए सरकार ने असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २००७ पेश किया है जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की परिकल्पना है। विधेयक के पारित होने की प्रत्याशा में सरकार ने ३ महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है ताकि एक कारगर सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क उपलब्ध हो।-

ग्रामीण क्षेत्रों का नवीकरण

4.1 भारत निर्माण

ग्रामीण आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार के लिए यूपीए सरकार ने 'भारत निर्माण' कार्यक्रम शुरु किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्हता पूरी करने वाले गांवों/बस्तियों में बिजली, सुरक्षित पेयजल, बारहमासी सड़क और टेलीफोन के साथ-साथ ग्रामीण आवास और सिंचाई की व्यवस्था का पर्याप्त विकास हो। सन् २००५ में 'भारत निर्माण' कार्यक्रम लागू किए जाने से फरवरी, २००८ तक १७,००० बस्तियों को हर मौसम में कारगर सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ४५,००० से अधिक गांवों में बिजली की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण गरीबों के लिए ४५ लाख घर बनाए गए हैं। साढ़े तीन लाख से अधिक बस्तियों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की गई है। ३८ लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई। पिछले ४ वर्षों के दौरान घर बनाने के लिए सहायता की राशि में लगातार वृद्धि करते हुए उसे २०,००० रूपये से ३५,००० रूपये कर दिया गया है। सिर्फ १२,००० गांवों को टेलीफोन से जोड़ने का काम शेष रह गया है। पिछले चार वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या दुगुनी हो गई है और शुल्क दरों में भारी कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन एवं इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन के साथ-साथ दूरसंचार के अन्य आधुनिक साधनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण दूरसंचार आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक व्यापक योजना लागू की गई है।

4.2 ग्रामीण रोजगार

यूपीए सरकार ने एक विधेयक पेश किया जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बना, जिसके तहत ग्रामीण गरीबों को १०० दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने की गारंटी दी गई। इतने बड़े पैमाने पर आज तक दुनिया भर में कहीं भी सामाजिक सुरक्षा का ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है।

4.2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

- यूपीए सरकार ने आरंभ में देश के २०० जिलों में इस कार्यक्रम को लागू करने के बाद इसे उत्तरोत्तर विस्तृत करते हुए अप्रैल, २००८ से सभी ६०४ ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया है।
- सालाना ३ करोड़ से अधिक लोगों को ३३० जिलों में रोजगार दिया जा रहा है। कार्यक्रम विस्तार के साथ और लोग लाभान्वित होंगे। १७ लाख से अधिक कार्यों की शुरुआत की गई है जिनमें ८ लाख से अधिक कार्य अप्रैल २००८ के मध्य तक पूरे हो चुके हैं।

4.3 कृषि एवं सहकारिता

यूपीए सरकार कृषि जगत में निम्न विकास दर, कर्ज में बढ़ोतरी और कृषि में घटते सरकारी निवेश के दौर के बाद २००६-०७ में उपलब्ध कृषि क्षेत्र की दुगुनी वृद्धि को सतत बनाए रखने का लक्ष्य रखती है। व्यापक पैमाने पर महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं ताकि किसानों को ऋण के साथ-साथ ऋण माफी भी मिल सके, उत्पादों के बेहतर दाम मिले तथा कृषि में सरकारी निवेश बढ़े। ११वीं योजना में कृषि एवं सिंचाई पर व्यय का लक्ष्य तीन गुना कर १,३८,००० करोड़ रूपये कर दिया गया है।

4.3.1 किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम

यूपीए सरकार ने पिछले चार वर्षों में अभूतपूर्व ५६ प्रतिशत की वृद्धि करते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ३७० रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है और धान के लिए ३३ प्रतिशत वृद्धि की है।

4.3.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

यूपीए सरकार ने ११वीं योजना के अंतर्गत १६ राज्यों के ३०५ जिलों में चावल, गेहूं एवं दालों का उत्पादन बढ़ाकर क्रमशः १०० लाख टन, ८० लाख टन और २० लाख टन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की है। इसके लिए ४,८०० करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान निर्धारित किया गया है।

4.3.3 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। राज्यों को कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। इस पर २५,००० करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

4.3.4 सिंचाई एवं वर्षा-सिंचित क्षेत्र का विकास

- यूपीए सरकार ने तीस्ता बराज (पश्चिम बंगाल), शाहपुर कंडी (पंजाब), बर्सर एवं उझ (जम्मू एवं कश्मीर), द्वितीय रावी व्यास लिंक (पंजाब), जिस्पा एवं रेणुका (हिमाचल प्रदेश), लखवर व्यासी (उत्तराखंड), किशाउ (हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड), नोआदेहांग एवं ऊपरी सियांग (अरुणाचल प्रदेश), कुलसी (असम), गोसीखुर्द (महाराष्ट्र) एवं केन-बेतवा (मध्य प्रदेश) परियोजनाओं को ६० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया है।

4.3.5 60,000 करोड़ रूपये की ऋण-माफी एवं ऋण-राहत

- यूपीए सरकार ने जून २००८ तक ऋण-माफी एवं ऋण-राहत की एक अभूतपूर्व योजना दी है। इसके तहत लगभग ४ करोड़ किसानों को मार्च, २००७ तक बैंकों द्वारा आबंटित कृषि ऋण, जो दिसंबर २००८ में अतिदेय थे, पर जिनका फरवरी २००८ तक भुगतान नहीं हो पाया था, के मामलों में ऋण-माफी और ऋण-राहत मिलेगी। इस योजना की अनुमानित लागत ६०,००० करोड़ रूपये है। अधिकतम २ हैक्टेयर भूधारक किसान पूर्ण ऋण-माफी के हकदार होंगे। • अन्य किसानों द्वारा बकाया ७५ प्रतिशत भुगतान कर देने पर २५ प्रतिशत की ऋण-राहत

दी जाएगी।

यूपीए सरकार द्वारा उसकी नई साख नीति के माध्यम से दिए गए कृषि ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी की गई है और अधिक से अधिक किसानों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही, कृषि ऋण और इसकी ब्याज दर को आसान बनाया गया है।

३१ आत्महत्या आशंकित जिलों के किसानों के लिए १६,००० करोड़ रूपये से अधिक की लागत का एक विशेष पैकेज बनाया गया है ताकि किसानों को ऋण के बोझ और सिंचाई की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके तथा खेती के लिए आवश्यक सामग्री और आमदनी के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हो सकें।

4.3.7 आत्महत्या आशंकित जिलों के लिए विशेष पैकेज

- ३१ आत्महत्या आशंकित जिलों के किसानों के लिए १६,००० करोड़ रूपये से अधिक की लागत का एक विशेष पैकेज बनाया गया है ताकि किसानों को ऋण के बोझ और सिंचाई की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके तथा खेती के लिए आवश्यक सामग्री और आमदनी के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हो सकें।

4.3.8 बागवानी

- यूपीए सरकार ने ३४० जिलों में बागवानी के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से २,७६,००० हैक्टेयर भूमि को बागवानी के लायक बनाया है और ५६,००० हैक्टेयर क्षेत्रफल के पुराने खेतों को फिर से खेती योग्य बना दिया है।

4.3.9 बागानी फसल

- यूपीए सरकार ने चाय के पुराने बागानों में पुनः चाय के पौधे लगाने और उसे नवजीवन देने के उद्देश्य से विशेष प्रयोजन चाय निधि की स्थापना की है। इससे चाय बागानों के 'एज-प्रोफाइल' में सुधार होगा। निधि से ११वीं योजना के अंतर्गत लगभग ८५,००० हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। एक पुनरुद्धार योजना के तहत ३३ चाय बागानों, जिनके बंद रहने से ३०,००० मजदूर प्रभावित थे, को पुनः खोल दिया गया है।

4.3.10 कपास

यूपीए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कई उपाय किए हैं, जैसे विपणन प्रांगणों का विकास, एक हजार बिनौला निकालने और पेरने के कारखानों का आधुनिकीकरण, आदि। इस प्रकार सरकार कपास की पैदावार ७० प्रतिशत बढ़ाने तथा उत्पादकता में ३५ प्रतिशत की वृद्धि करने में सफल रही है। इससे कपास आयात में कमी आई है और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

4.3.11 तिलहन, दलहन एवं मक्का

यूपीए सरकार ३ वर्षों की अवधि में प्रमाणित बीजों का उत्पादन दुगुना कर एकीकृत तिलहन, 'ऑयल पाम', दलहन एवं मक्का विकास कार्यक्रम का विस्तार करने में प्रयासरत है।

4.3.12 गन्ना एवं चीनी उद्योग

- यूपीए सरकार द्वारा दिए गए एकमुश्त सहायता पैकेज को तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा अपनाए जाने के फलस्वरूप गन्ने की पुरानी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया तथा वर्ष २००६-०७ एवं वर्ष २००७-०८ में गन्ने का उत्पादन भी बढ़ गया।

4.3.13 बांस

- बांस क्षेत्र के समग्र विकास और प्रति हैक्टेयर उत्पादकता को २-३ टन से बढ़ा कर १८ टन करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई है।

4.3.14 पशुधन

- यूपीए सरकार द्वारा चिन्हित जिलों में पशुधन बीमा योजना कार्यान्वित की गई है। इसके तहत वर्णसंकर एवं अधिक उत्पादन वाले मवेशियों तथा भैंसों को प्रीमियम पर ५० प्रतिशत सरकारी अनुदान के साथ बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

4.3.15 कृषि अनुसंधान

- यूपीए सरकार ने कृषि संसाधन से प्राप्त ज्ञान का खेतों में उपयोग सुनिश्चित करनें के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना की शुरुआत की है। लगभग सभी ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है।

4.3.16 शिक्षा

- यूपीए सरकार ने ३४ राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय, ५ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और ३ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विकास एवं सशक्तिकरण की एक योजना कार्यान्वित की है और जम्मू में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना का काम शुरु किया है।

4.3.17 कृषि विस्तार कार्य

यूपीए सरकार द्वारा राज्यों का विस्तार में सहयोग हेतु एक योजना लागू की गई है ताकि जिला पर स्थापित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों के माध्यम से विस्तार कार्य किया जा सके।

4.3.18 उर्वरक

- यूपीए सरकार ने उर्वरक की बढ़ती मांग के मद्देनजर व्यापक उपाय किए हैं। देश के अंदर उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया है, दीर्घकालिक आयात व्यवस्था की गई है और उत्पादन/आपूर्ति के लिए विदेशों में भी संयुत उपक्रमों को अपनाया है। अगले तीन-चार वर्षों में फीडस्टॉक के रूप में शत-प्रतिशत गैस के उपयोग जैसे परिवर्तन कर क्षमता बढ़ाने और उत्पादन की लागत घटाने का प्रयास जारी है।

पर्यावरण और प्रशासन

- यूपीए सरकार ने नई राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अपनाई है ताकि सभी संगत क्षेत्रों में नई विकास की गतिविधियों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी सोच समाविष्ट हो सके। इस नीति में एक आमूल परिवर्तन यह हुआ है कि इस सच्चाई को स्वीकारा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे दृढ़ आधार यह है कि किसी भी संसाधन पर आश्रित लोग उसके दोहन के बजाए उसके संरक्षण के जरिए बेहतर जीविका प्राप्त कर सकें।

5.1 वन्यजीव संरक्षण

यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है ताकि बाघों का बेहतर संरक्षण हो। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना की गयी है।

5.2 हरित भारत

यूपीए सरकार ने 'हरित भारत' नामक एक कार्यक्रम को स्वीकृति दी है जिसके तहत ६० लाख हैक्टेयर उजड़ गये वनों में अगले १० वर्षों के दौरान व्यापक रूप से वृक्षारोपण होगा। इसी वर्ष ३० लाख हैक्टेयर पर यह काम शुरु किया जाना लक्षित है। इस उद्देश्य से एक प्रतिपूरक वनीकरण निधि और एक प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण की स्थापना के लिए संसद में विधेयक पेश करने की मंजूरी दे दी गयी है।

5.3 जलवायु परिवर्तन

- यूपीए सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर तत्परता से कदम उठाया है तथा जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद का गठन किया है जो जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने और अनुकूलन के लिए उपयुक्त रणनीतियों को लागू करेगी। जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। भारत ग्रीनहाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को विकसित देशों के प्रति व्यक्ति औसत उत्सर्जन से कम रखने के लिए तैयार है।

5.4 जल संरक्षण

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर जल संरक्षण कार्यों को अपनाया जा रहा है।

शासन एवं आम समाज

6.1 सुधार

यूपीए सरकार द्वारा प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधारों को शुरु और कार्यान्वित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबार में आमूल सुधार, सूचना अधिकार के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन की कई परियोजनाओं में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

6.1.1 प्रशासनिक सुधार

यूपीए सरकार ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया है जिसने भारत में लोक प्रशासन के व्यापक सुधार के लिए कई अनुशंसाएं की है। अग्रिम कार्यवाही के लिए इनका परीक्षण जारी है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की जिम्मेदारी और क्षमता में सुधार के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मध्य सेवा काल में प्रशिक्षण, गहन समीक्षा, प्रदर्शन मूल्यांकन और पदोन्नति संबंधी नई नीतियां अपनाई गई हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार एवं नागरिक सेवा दिवस की शुरुआत की गई है।

यूपीए सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सफलतापूर्वक सकारात्मक दिशा दी गई है। बैंकों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक प्रबंधकीय एवं व्यावसायिक स्वायत्तता दी गई है।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उम्मीद है कि रिपोर्ट सरकारी कार्मिकों की वैध आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होगी।

यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू कर दिया है और इस प्रकार आम जनता को सरकार के काम-काज को समझने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों की गतिविधियां भी अधिक पारदर्शी हो गई हैं। इस कानून से आम जनता न्याय पाने और अपनी पुरानी शिकायतों के निपटान में सक्षम हो गई है।

6.1.2 इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन

- यूपीए सरकार ने आयकर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर, रेल आरक्षण, भारतीय डाक मासिक आमदनी योजना के तहत निवेशकों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक जमा, राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र आदि के डिमैटेरियलाइजेशन (कागज रहित) से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।
- एमसीए २१ परियोजना के तहत कंपनी रजिस्ट्रार से संबंधित सभी सेवाएं अब इंटरनेट पर सुलभ हैं।

6.1.3 न्याय व्यवस्था में सुधार

- यूपीए सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जिसके तहत शाम ढलने के बाद महिला को गिरफ्तार करने पर प्रतिबंध, पुलिस हिरासत में मृत्यु एवं बलात्कार की अनिवार्य न्यायिक जांच लंबी अवधि तक कैद में रहे विचाराधीन कैदियों को आजाद करने के प्रावधान, अभियोजन के लिए राज्य महानिदेशालय की स्थापना या आरोपी द्वारा आरोप स्वीकार कर लेने के बदले में कम दंड के समझौते की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव हैं।

6.2 पंचायती राज

- स्थानीय विकास नियोजन के लिए अनाबद्ध राशि का प्रावधान कर यूपीए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। साथ ही, सेवा प्रदान करने की प्रणाली को नई दिशा देकर इसमें पंचायती राज व्यवस्था को अहमियत दी है।

6.2.1 गोल मेज सम्मेलन एवं विकास प्रक्रिया में पंचायतों की केन्द्रीय भूमिका

- यूपीए सरकार ने राज्य पंचायती राज मंत्रियों के साथ ७ गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन किया ताकि एक आम सहमति बन सके। इसके परिणामस्वरूप पंचायतों को सौंपी जाने वाली धनराशियों एवं जिम्मेवारियों की योजनाएं हर राज्य के लिए तैयार की जा सकी हैं।

6.2.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

४००० करोड़ रूपये प्रतिवर्ष से अधिक आबंटन से स्थापित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को २५० चिन्हित पिछड़े जिलों में पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। पिछले ४ वर्षों में राष्ट्रीय सम विकास योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत राज्यों को ८,००० करोड़ रूपये की राशि निर्गत की गई है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन को अपनाया गया है।

६.२.३ पंचायतों के माध्यम से वितरण प्रणाली को नई दिशा

पंचायतों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने और उस पर निगरानी रखने में केन्द्रीय भूमिका दी गई है। कम-से-कम आधा कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है जिसके लिए धनराशि भी पंचायतों को ही दी जाती है।

6.3 शहरी नवीकरण

6.3.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण ा मिशन

यूपीए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आरंभ किया है। यह स्वतंत्रता के बाद शहरी विकास का सबसे बड़ा प्रयास है। इसके अंतर्गत ५४ शहरों में ३०,००० करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाएं लागू हो रही हैं। अप्रैल २००८ के मध्य तक शहर के गरीबों के लिए १० लाख से अधिक घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। गरीबों की मौलिक जरूरतों, जैसे आवास, जल आपूर्ति, सफाई, झुग्गी-झोंपड़ी में सुधार, सामुदायिक शौचालय/स्नानघर आदि के प्रावधान पर जोर दिया गया है ताकि आम जनता के जीवन स्तर में सुधार हो।

6.3.2 समेकित वित्त विकास योजना

यूपीए सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वित्त विकास निधि की स्थापना के लिए एक योजना लागू की गई है ताकि शहरी स्थानीय निकायों को अधिक ऋण प्राप्त हो सके और वे राज्य स्तरीय समेकित वित्त के माध्यम से बाजार से ऋण प्राप्त कर सकें।

6.3.3 मेट्रो एवं उपमहानगरीय रेल सेवा

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना सफलतापूर्वक आरंभ हो चुकी है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के दूसरे चरण का भी अनुमोदन कर दिया है जिसके तहत गुड़गांव और नोएडा तक इसका विस्तार हो जाएगा। साथ ही, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बीच एक मेट्रो लिंक अनुमोदित किया गया है।

6.3.4 छावनियां

नये छावनी अधिनियम, २००६ में छावनी बोर्डों की गतिविधियों को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य से निर्वाचित और गैर-निर्वाचित सदस्यों के बीच समानता लाई गई है। बोर्ड की बैठकों में स्थानीय सांसद/विधायक को विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई है। इस वर्ष नए अधिनियम के तहत चुनाव होंगे।

6.4 केन्द्र-राज्य संबंध

- तीन दशकों के बाद यूपीए सरकार ने केन्द्र-राज्य संबंधों पर एक आयोग का गठन किया है। आयोग ने काम शुरु कर दिया है।
- महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिनमें केन्द्र-राज्य तालमेल आवश्यक हो, सामूहिक रूप से विचार-विमर्श कर एक आम समझ और कारगर रणनीति बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मंचों पर मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श का आयोजन किया जाता रहा है।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति इससे बेहतर कभी न थी। ११वें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अंतर्गत कर अंतरण की नई योजना के परिणामस्वरूप राज्यों की भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है। यह २००३-०४ में ६५,७८४ करोड़ से बढ़ कर इस वर्ष १,७८,७६५ करोड़ रूपये हो गई है। इसी अवधि में राज्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान सहायता राशि ४७,३२० करोड़ रूपये से बढ़ कर १,२४,७४५ करोड़ रूपये हो गई है।

विकास की ओरः उत्तर पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर

7.1 उत्तर पूर्व

7.1.1 शांति सुनिश्चित करने के प्रयास

- यूपीए सरकार ने हिंसा का रास्ता अपनाने वाले समूहों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ कर बिना किसी शर्त बातचीत के लिए आगे आएं। कई संगठन अपनी गतिविधियों को स्थगित कर बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। इससे कुछ लोगों में अलग-थलग पड़ने का एहसास कम हो गया है। बड़ी संख्या में ब्रू/रिचांग जनजाति के लोग मिजोरम वापस आ गए हैं तथा उनका पुनर्वास हो गया है। विद्रोही संगठनों की गतिविधियों की समस्या के समाधान के लिए बांग्लादेश, म्यान्मार और भूटान के साथ राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा के किनारे सड़क बनाने के काम को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

7.1.2 सड़कें

- यूपीए सरकार ने उत्तर-पूर्व में ८,७३७ कि.मी. लंबाई की सड़कों के सुधार के लिए एक विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम शुरु किया है। इस परियोजना के पहले चरण, जिसमें २,३०४ कि.मी. सड़क पर काम होगा, को स्वीकृति दे दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर पर काम जारी है।

7.2.3 रेलमार्ग

- यूपीए सरकार ने गुवाहाटी जाने वाले मुख्य रेलमार्ग के बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी खंड के शेष ८०० कि.मी. के विद्युतीकरण और ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में रेल-सह-सड़क पुल बनाने का काम शुरु किया है। लमडिंग-सिलचर एवं रंगिया-मर्कोंगसेलेक में गेज परिवर्तन और कुमारघाट-अगरतला-सबरूम, जीरीबम-तुपुल (इम्फाल रोड), भैरवी-सैरंग (आईजोल) और ईटानगर-हरौती में नयी रेलवे लाईन के निर्माण का काम शुरु किया गया है ताकि प्रदेश राज्यों की राजधानियां बेहतर जुड़ सकें। इसके अलावा अगरतला-सबरूम रेल लाईन की स्वीकृति से भविष्य में चिटगांव बंदरगाह से सबरूम के लिए रेल संपर्क की संभावना भी बन गई है।

7.1.4 विमानपत्तन

- उत्तर-पूर्व परिषद उत्तर-पूर्व क्षेत्र के १८ विमानपत्तनों के उन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ सहयोग समझौता कर रहा है। असम के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नए विमानपत्तन बनाए जाएंगे।

7.1.5 अंतर्देशीय जलमार्ग

- यूपीए सरकार ने बराक नदी के लखिपुर-भांगा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इससे बराक घाटी में लखिपुर, सिलचर और बदरपुर जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र हल्दिया एवं कोलकाता बंदरगाहों से बेहतर जुड़ जाएंगे।

7.1.6 बिजली

- प्रधान मंत्री ने देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना ३,००० मेगावाट, की दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना के साथ-साथ इसी वर्ष अरुणाचल प्रदेश में ११० मेगवाट की पारे पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी है।

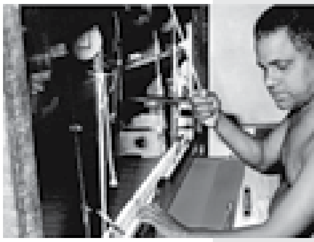

7.1.7 उद्योगों का प्रोत्साहन

- यूपीए सरकार ने उत्तर-पूर्व के लिए एक अधिक उदार नई औद्योगिक और निवेश नीति की घोषणा की है जिसमें पूंजीगत व्यय पर अनुदान को दुगुना कर दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया है।

7.1.8 उत्तर-पूर्व के लिए निश्चित बजट प्रावधान

यूपीए सरकार ने उत्तर-पूर्व के लिए बजट के प्रावधान में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। पिछले ५ बजट के दौरान तीन गुनी वृद्धि के साथ यह १६,४४७ करोड़ रूपये हो गया है।

7.1.9 स्वास्थ्य

यूपीए सराकर ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों पर विशिष्ट ध्यान दिया है। क्षमता विकास हेतु उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है।

7.1.10 शिक्षा

- यूपीए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत अन्य राज्यों को दी जा रही ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की तुलना में उत्तर-पूर्व के राज्यों को ६० प्रतिशत सहायता दी है।
- मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक कानून बनाया गया है ताकि परिवर्तित विश्वविद्यालयों का तीव्र विकास हो और उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय सुनिश्चित हो जाए।

7.1.11 शहरी नवीकरण

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत उत्तर-पूर्व के बड़े-छोटे शहरों की परियोजनाओं हेतु ६० प्रतिशत तक केन्द्रीय अनुदान दिया जा रहा है।

7.1.12 बांस

उत्तर-पूर्व राज्यों को राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है।

7.1.13 अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन पैकेज

- उत्तर-पूर्व में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए यूपीए सरकार ने एक प्रोत्साहन पैकेज लागू किया है।

7.2 जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू एवं कश्मीर के हालात में स्पष्ट सुधार दिख रहे हैं। सरकार आतंकवाद और सीमा पार से हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और इस चुनौती का सामना करते हुए राज्य में स्थायी शांति बहाल करने को कृतसंकल्प है। इस उद्देश्य से एक समग्र एवं बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है। २४,००० करोड़ रूपये की लागत से प्रधान मंत्री पुनर्निर्माण योजना को तत्परता से लागू किया जा रहा है। बेहतर संचार-नेटवर्क, अधोसंरचना विकास, विद्युत व्यवस्था में सुधार और रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसी योजना के एक भाग के रूप में राज्य में कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए एक आवासीय परियोजना

भी कार्यान्वित की जा रही है। सरकार एक समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है ताकि सभी वर्गों के लोगों के बीच विश्वास कायम हो सके, लोग नियंत्रण रेखा के आर-पार आसानी से आ-जा सकें तथा जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान देते हुए एक बेहतर प्रशासन कायम हो सके।

7.2.1 बिजली

- ३६० मेगावाट की दुलहस्ती परियोजना चालू कर दी गई है। कई अन्य परियोजनाएं जैसे २४० मेगावाट की उरी-२ परियोजना, १२० मेगावाट की सेवा-२ परियोजना और ४५० मेगावाट की बगलिहार परियोजना पर काम को तेज कर दिया गया है। लद्दाख क्षेत्र की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए नीमो बाजगो एवं चुटक जलविद्युत परियोजनाएं (८६ मेगावाट) स्वीकृत की गई हैं। ३३० मेगावाट की किशनगंगा परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। ये परियोजनाएं राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करेंगी।

7.2.2 सड़क

- श्रीनगर-कारगिल-लेह मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया हैं तथा उसके उन्नयन का काम चल रहा है।
- मनाली से लेह के लिए रोहतांग दर्रे से गुजरने वाले एक वैकल्पिक बारहमासी मार्ग का विकास किया जा रहा है।
- मुगल मार्ग, कटरा मार्ग (वैष्णो देवी के लिए) एवं पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत ली गई अन्य सड़कों के निर्माण का काम पूरी तेजी से चल रहा है।

7.2.3 विमानन

- श्रीनगर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया गया है तथा इसकी अधोसंरचना के उन्नयन का काम चल रहा है।
- कारगिल एवं श्रीनगर के बीच उड़ानों की क्षेप बढ़ा दी गई है।
- जम्मू एवं लेह के विमानपत्तनों के सुधार हेतु कार्य किए जा रहे हैं।

7.2.4 शहरी अधोसंरचना

- श्रीनगर एवं जम्मू में जल आपूर्ति, जल निकासी एवं सीवर व्यवस्था के लिए एशियाई विकास बैंक से प्राप्त सहायता से परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है तथा कार्य जारी है।

7.2.5 रेलमार्ग

- जम्मू-ऊधमपुर रेलमार्ग खंड को चालू कर दिया गया है तथा वर्ष २००८ में ही ऊधमपुर-कटरा खंड खोला जाना लक्षित है। कटरा-काजीगुंड-बदगाम खंड पर काम चल रहा है।
- जम्मूतवी-जलंधर रेलमार्ग पर दूसरी लाइन डालने का काम वर्ष २००८ में पूरा होने की संभावना है।

7.2.6 शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है।
- १५ नए महाविद्यालय एवं ६ नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चालू हो गए हैं। १० अन्य महाविद्यालयों एवं ५ नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया जा चुका है।
- संपूर्ण साक्षरता अभियान को सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है।

7.2.7 रोजगार एवं आय वृद्धि

- आंगनवाड़ियों, इंडिया रिजर्व बटालियनों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल बटालियनों एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के माध्यम से प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत लगभग २०,०० प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं।
- पर्यटन एवं हस्तशिल्प उद्योग, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कृषि आदि को व्यापक समर्थन देकर पर्याप्त स्वरोजगार और आय वृद्धि के अवसर पैदा किए जा रहे हैं।

7.2.8 राहत एवं पुनर्वास

- गोल मेज सम्मेलन की अनुशंसाओं को साकार करने के लिए प्रधान मंत्री ने विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच विश्वास कायम करने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसके तहत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों समेत पिछले १८ वर्षों में हुई हिंसा के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए एक सहायता योजना लागू की गई है। हिंसा के शिकार परिवारों के जिन लोगों को पात्रता के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकी है, उन्हें वैकल्पिक सहायता देने के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है। घाटी में वापस लौटने के इच्छुक विस्थापित कश्मीरी परिवारों को घर के लिए ७.५ लाख रूपये प्रदान किए जाएंगे और खेती तथा बागबानी की बहाली के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। शिविरों में रहने वालों को मासिक राहत जारी रखते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता दी जाएगी।
- घाटी में आवासीय इकाइयों के प्रावधान के अतिरिक्त जम्मू के शिविरों में रहने वाले ५,००० से अधिक कश्मीरी विस्थापितों के लिए दो कमरों की आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है।

आर्थिक पुनरुत्थान

8.1 औद्योगिक विकास, निवेश एवं वित्त बाजार

आज यह संभव है कि एक ही पीढ़ी के जीवन में गरीबी का उन्मूलन हो जाए। यदि अर्थव्यवस्था ६ से १० प्रतिशत सालाना दर से बढ़ती रही तो राष्ट्रीय आय लगभग ७ सालों में दुगुनी हो जाएगी। यदि इस वृद्धि के साथ बच्चों की शिक्षा तथा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रोत्साहक रणनीतियां लागू हुईं तो गरीबी उन्मूलन के प्रयास पर निस्संदेह सकारात्मक असर होगा। यूपीए सरकार ने गरीबी उन्मूलन के इस सपने को साकार करने की दिशा में काम किया है। पिछले ३ वर्षों में दर्ज विकास दर स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ है। पिछले ४ वर्षों में लगभग ६ प्रतिशत वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था निस्संदेह तेज वृद्धि के दौर में आ चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की सालाना दर लगभग दोगुनी हो कर ७ प्रतिशत हो गई है। ११वीं योजना में औसत ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य है।

8.1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

यूपीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित किया है। कुल कारोबार एवं लाभ दोनों में सतत सुधार देखा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों का लाभ तीन वर्षों में तीन गुना बढ़ कर वर्ष २००६-०७ में १५,५६७ करोड़ रूपये हो गया है।

8.1.2 विनिर्माण

यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद और उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति का गठन किया है ताकि विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण हो।

8.1.3 कर संबंधी सुधार

- यूपीए सरकार ने पिछले ४ वर्षों में यह साबित कर दिया है कि कर की दरों में कटौती के बावजूद कर राजस्व में उछाल लाया जा सकता है। पिछले चार वर्षों से सकल कर राजस्व में सालाना २० से २५ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। वर्ष २००३-०४ में कर का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अनुपात ६.२ प्रतिशत से बढ़कर वर्ष २००७-०८ में १२.५ प्रतिशत से बढ़कर वर्ष २००७-०८ में १२.५ प्रतिशत हो गया है।
- आयकर में उल्लेखनीय छूट दी गई है, विशेष कर महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

८.१.४ कॉरपोरेट मामले

- इलेक्टॉनिक अधिशासन की परियोजना एमसीए २१ के तहत इंटरनेट के माध्यम से सभी लेनदेन संभव बनाकर व्यवसाय जगत, शेयरधारकों, निवेशकों, व्यवसायियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं विभागीय कर्मचारियों के काम काज से संबंधित कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन कर दिया गया है।
- एक नये प्रकार के निगमित निकाय, सीमित देयता भागीदारी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप), की व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से नया कानून बनाने के लिए संसद में पेश किए जाने हेतु एक विधेयक तैयार है। इससे व्यवसायियों एवं ज्ञान क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए निगमन का उपयुक्त माध्यम मिलेगा और सेवा क्षेत्र के विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे। निवेशकों को आवश्यक शिक्षा देने और उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से निवेशक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है तथा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष तैयार किया गया है। साथ ही, आर्थिक मामलों में चूक करने वालों के नाम वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वेब रजिस्ट्री का प्रावधान किया गया है। निवेशकों की शिकायतों के प्रभावी निपटान के लिए भी एक वेबसाइट कार्यरत है।

८.१.५ निवेश का बेहतर परिवेश

- अप्रैल २००४ से दिसंबर २००७ के बीच कुल पौने चार वर्ष की अवधि में कुल विदेशी सांस्थानिक निवेश पिछले लगातार १२ वर्षों के कुल निवेश के डेढ़ गुना से अधिक है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त उछाल के साथ पूंजी प्रवाह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ५ प्रतिशत से भी अधिक हो गया है।

८.१.६ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

- यूपीए सरकार की पहल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, २००६ कानून बना। इसके तहत पहली बार उद्यम की परिकल्पना में उत्पादन के साथ-साथ सेवा को भी कानूनी दायरे में लाया गया है। सूक्ष्म उद्यमों के लघु उद्यमों के मध्यम उद्यमों में उत्तरोत्तर विकास की कानून में पही बार उपयुक्त व्यवस्था की गई है। इस श्रेणी के उद्यमों से विचार-विमर्श के लिए कानून में व्यवस्था दी गई है। ऐसे उद्यमों की स्थापना और प्रोत्साहन के लिए एक निधि प्रावधानिम की गई है। ऐसे उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं का सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने और भुगतान में विलंब की आशंका को दूर करने के लिए भी कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

८.१.७ निर्यात से जुड़े उद्योग

- सरकार द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने मार्च २००८ के अंत तक लगभग १,८०,००० लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है जबकि अनुमानतः इसका दोगुना अप्रत्यक्ष रोजगार सुनिश्चित हुआ है। विशेष आर्थिक क्षेत्र ६७,००० करोड़ रूपये से अधिक का निवेश आकर्षित करने में सफल रहे। वर्ष २००७-०८ के दौरान ६४,००० करोड़ रूपये से अधिक का निर्यात हुआ।

८.१.८ निर्यातकों के लिए राहत के उपाय

पिछले वर्ष अमेरिकी डॉलर की तुलना में रूपये के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि से निर्यात पर बहुत असर पड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूपीए सरकार ने निर्यातक समुदाय को राहत देने के लिए कई उपाय किए।

८.१.९ सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवाएं

- पिछले ४ वर्षों में भारत से सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवा के निर्यात में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इससे १२ लाख शिक्षित युवाओं को प्रत्यक्ष और अतिरिक्त ८० लाख युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
- सॉफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क योजना के तहत मार्च २०१० तक आयकर में छूट का प्रावधान कर दिया गया है।

८.१.१० इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी हाडवेयर एवं दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन

- यूपीस सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एवं अन्य सूक्ष्म व नैनो टेक्नालाजी उत्पादन उद्यमों की स्थापना हेतु निवेश आकृष्ट करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना लागू की है। इसके तहत ६०,००० करोड़ रूपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं।

८.१.११ रसायन एवं पेट्रोरसायन

- पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों के लिए एक योजना अपनाई गई है ताकि विश्वस्तरीय डेवलपर एवं निवेशक इन क्षेत्रों में भागीदारी दे सकें।

८.१.१२ खनन उद्योग

- नई खनन नीति अपनाई गई है जिससे इस क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगे। साथ ही लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार होगा, विशेषकर सर्वेक्षण लाइसेंस से पूर्वेक्षण लाइसेंस व उसके पश्चात उत्खनन लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में सरलीकरण के जरिए।
- भारतीय भूवैज्ञानिक (जीएसआई) सर्वेक्षण का आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन किया जा रहा है ताकि भूभाग एवं समुद्री भाग में खनिज खोजने की क्षमता का विकास हो।

८.१.१३ इस्पात उद्योग

- सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के लाभ में तेज वृद्धि हुई है। इससे उत्साहित भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण विस्तार योजनाओं पर काम शुरु कर दिया है। अब भारत विश्व का ५वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश हो गया है जबकि सन् २००५ में यह ८वें स्थान पर था। सन् २०१५ तक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। सन् २००५ में लागू नई राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत ११ करोड़ टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य वर्ष २०११-१२ तक ही हासिल कर लिए जाने की उम्मीद है।

८.१.१४ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

- यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ लागू किया है ताकि खाद्य संबंधी कानून एकीकृत किया जा सके तथा आत्मनिर्भरता के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विकास हो सके। पहले खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी १३ अलग-अलग कानून लागू थे।
- यूपीए सरकार ने फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग उद्योग स्थापित करने के लिए पांच वर्ष तक कर-मुक्ति और अन्य रियायतों का प्रावधान किया है।
- खाद्य प्रसंस्करण को वित्तीयन के दृष्टिकोण से प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है तथा नाबार्ड के माध्यम से उसके पुनर्वित का प्रावधान कर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कई वस्तुओं को उत्पाद एवं सीमा शुल्क में छूट के साथ-साथ कई अन्य राहतें प्रदान की गयी हैं।

८.१.१५ वस्त्र उद्योग

- इस क्षेत्र के लिए कर राहत सहित एक बड़ा पैकेज प्रदान किया गया है। शुल्क दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है ताकि देश के अंदर विकास एवं अधिकतम मूल्यवर्धन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मानव-निर्मित फिलामेंट और स्टेपल फाइबर के अतिरिक्त पूरी मूल्यवर्धित श्रृंखला को उत्पाद कर से छूट का विकल्प दिया गया है। मशीनों एवं उनके कल-पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है। अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान भी उपलब्ध करवाया

गया है। मशीन, कच्चा माल और कल-पुर्जों पर कर में कटौती की गई है। पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है।

8.1.16 हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग

- बुनकरों की सहायता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस उद्देश्य से कलस्टरों विकास केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, अधिक यार्न डिपो बनाए जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहयोग दिया जा रहा है, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा का प्रावधान किया जा रहा है, और ब्राण्ड के प्रचार-प्रसार के लिए एक नया 'हैंडलूम मार्क' विकसित किया गया है।
- एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत ५,००० से अधिक हथकरघों वाले २५० हथकरघा क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है।
- शिल्पियों एवं उनके परिवारों को बीमा सुरक्षा देने के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। ११वीं योजना के तहत ४० लाख शिल्पी इससे लाभान्वित होंगे।

8.1.17 पटसन

- कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निरंतर बढ़ाते हुए वर्ष २००८-०९ में १,२५० रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वर्ष २००४-०५ में यह ८६० रूपये था।
- पटसन की पर्याप्त मांग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चीनी एवं अनाज रखने के लिए अनिवार्य रूप से पटसन की बोरी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।
- पहली बार व्यापक राष्ट्रीय पटसन नीति की घोषणा की गई है ताकि पटसन की मांग में बढ़ोतरी अरै बुनकरों के हित की रक्षा हो।
- भारतीय पटसन निगम की पुनर्संरचना का काम शुरु किया गया है।

8.2 ऊर्जा

8.2.1 कोयला

- प्रतिरक्षा, रेलवे, बिजली एवं उर्वरक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई कोयला वितरण नीति अधिसूचित की गई है।
- पिछले ४ वर्षों में उत्पादन में व्यापक सुधार हुआ है और कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के लाभ में सुधार हुआ है। कोल इंडिया के साथ साथ निजी, संयुक्त एवं सरकारी क्षेत्रों के निकायों को बड़ी संख्या में कोल ब्लॉक दिए गए हैं ताकि आने वाले दिनों में ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं का समय पर विकास किया जा सके।

8.2.2 बिजली

- ११वीं योजना के तहत अतिरिक्त ७८,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजन का लक्ष्य है। कुल ६०,००० मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की परियोजनाओं का काम चालू है।
- यूपीए सरकार ने कई अन्य उपाय किए हैं जिनमे शामिल है कोल ब्लॉक का आबंटन, जिनसे अनुमानतः ६८,००० मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा सकेगा।
- कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी नौ स्थानों का चयन किया गया है। इनमें प्रत्येक की क्षमता ४,००० मेगावाट होगी। सासन और मुंधरा परियोजनाओं पर काम चालू हो गया है।

8.2.3 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

- यूपीए सरकार ने ऊर्जा सक्षमता बढ़ाने पर हर संभव जोर दिया है। इस उद्देश्य से तेल एवं गैस के घरेलू भंडारों की तीव्र खोज के साथ-साथ विदेशों में भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ब्लॉक अर्जित करने का काम जारी है।
- सरकार द्वारा ४ वर्षों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस खोज के लिए ७२ ब्लॉक प्रदान किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप खोज हेतु लिए कुल क्षेत्र में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १५ ब्लॉक में तेल एवं गैस के विशाल भंडारों की खोज हुई है।

8.2.4 नाभिकीय ऊर्जा

- नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता ४,१२० मेगावाट बढ़कर वर्ष २००६ तक ६७८० मेगावाट और वर्ष २०११ तक ७,२८० मेगवाट हो जाएगी।

8.2.5 नई एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा

- यूपीए सरकार ने पिछले ४ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान क्षमता में जो वृद्धि हुई है वह पिछले १५ वर्षों की तुलना में हुई वृद्धि से अतिरिक्त 'ग्रिड-इंटरएक्टिव' नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता का विकास किया गया है जबकि इससे पहले स्थापित कुल क्षमता लगभग ४,८०० मेगावाट थी। इस प्रकार भारत इस मामले में एशिया में अग्रणी राष्ट्र हो गया है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भी विश्व में इसका चौथा स्थान हो गया है।

8.3 अधोसंरचना

११वीं योजना के तहत अधोसंरचना के विकास में कुल निवेश का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के ५ प्रतिशत से बढ़ाकर ९ प्रतिशत कर देना है। अधोसंरचना के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी और जहां संभव हो निजी क्षेत्र की पूरक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

8.3.1 सड़क

- यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) को अपनाया है। एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है जिसके तहत एनएचडीपी के विभिन्न चरणों में ३४,००० कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए २,३६,००० करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।

8.3.2 विमानपत्तन एवं विमानन

- हाल के कुछ वर्षों में नागर विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। हवाई सेवा अब आम आदमी की पहुंच में आ गई है। यूपीए सरकार ने विमानपत्तनों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी है तथा इस क्षेत्र में कुशल कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी की है। हैदराबाद में एक नये अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया है। वर्ष २००८ में बंगलुंरू में भी एक नया विमानपत्तन काम करने लगेगा। दिल्ली एवं अन्य महानगरों में नए टर्मिनलों के निर्माण का काम जारी है। वर्ष २०१० तक मुंबई और दिल्ली दोनों विमानपत्तनों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

8.3.3 पोत

- यूपीए सरकार ने पोतों की आधारभूत क्षमता के विकास का व्यापक कार्यक्रम शुरु किया है। समुद्री अधोसंरचना उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम शुरु किया गया है। इसके तहत ३८७ परियोजनाएं तैयार की गई हैं। वर्ष २०११-१२ तक १००,००० करोड़ रूपये की लागत से २७६ परियोजनाओं को लागू करने का लक्ष्य है। डूब क्षेत्र में सुधार के लिए चैनलों को गहरा करने, पोत विकास, पोत उपकरण एवं पोतों को जोड़ने के उद्देश्य से ये परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। ३२ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं जबकि १३१ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- कोचीन पोत स्थित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल का २,००० करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से विकास किया जा

रहा है।

8.3.4 नौ–परिवहन

- सेतुसमुद्रम नौ-परिवहन मार्ग परियोजना पर 'एडम्स ब्रिज' को छोड़कर काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने एडम्स ब्रिज पर काम पर रोक लगा दी है।
- नौ-परिवहन पर भार (टनेज) के अनुसार कर लगाने से माल भार में वृद्धि हुई है तथा इसके और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।
- भारतीय नौ-परिवहन निगम ने २८ नए जहाजों की खरीद का आदेश दिया है। इस प्रकार नौ-परिवहन क्षमता के स्तर में जो वृद्धि होगी वह हाल के वर्षों में अभूतपूर्व है।
- कच्छ की खाड़ी में यातायात नियंत्रण के लिए माइक्रोवेव लिंक आधारित जहाज यातायात प्रणाली की स्थापना की जा रही है।

8.3.5 अंतर्देशीय जलमार्ग

अंतर्देशीय जल परिवहन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है। संसद में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें तालचर-धमरा एवं ईस्ट कोस्ट कनाल, काकीनाड़ा-पुदुचेरी और बराक नदी की कुल १,८३६ कि.मी. लंबाई के जलमार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने का प्रावधान है जिसके बाद इन्हें और २,००० करोड़ रूपये की लागत से विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त पटना और गुवाहाटी में विकास कार्य, मौजूदा सभी तीन राष्ट्रीय जलमार्गों में रात में नौ-परिवहन की सुविधा शुरु करने और उत्तर-पूर्व में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास की एक नई योजना लागू की गई है। इन जलमार्गों से पारादीप, धमरा, कोलकाता और हल्दिया पोतों को नजदीकी शहरों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्ग में ७० प्रतिशत की वृद्धि होगी।

8.3.6 रेलमार्ग

- यूपीए सरकार ने भारतीय रेल के वित्तीय एवं तकनीकी प्रदर्शन में बेहद सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित किए हैं।
- मानवीय संवेदना के साथ सुधार कार्य किए गए हैं। इसमें सामाजिक दायित्वों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। वर्ष २००६-०७ में अब तक का सर्वाधिक उत्पादकता-संबद्ध ७० दिनों का बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित ३६,००० रिक्तियों पर नियुक्ति की गई है। बड़ी संख्या में विकलांगों को नौकरियां दी गईं। भारतीय रेल में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी के लिए एक अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। बेहतर यात्री सुविधा और यात्री भाड़े में कमी, विशेष कर गरीब वर्ग के लोगों के लिए की गई है।

8.3.7 दूरसंचार

- ४ वर्षों में दूरभाष कनेक्शन की संख्या ४ गुना बढ़ गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अधोसंरचना की स्थापना और प्रबंधन के लिए सहयाता प्रदान करने हेतु एक योजना की शुरुआत की गई है ताकि किफायती दरों पर मोबाइल सेवा का शीघ्र विस्तार हो।

8.3.8 अधोसंरचना विकास हेतु प्रोत्साहक

ऐसी अधोसंरचना विकास योजनाओं को वित्तीय तौर पर संभाव्य के लिए अनुदान की एक योजना लागू की गई है जो वित्तीयन के दृष्टिकोण से संभाव्य नहीं है परंतु आर्थिक रूप से लाभदायक है। बैंक एवं वित्तीय संस्थानों, जो वर्तमान में लंबी अवधि के ऋण देने में असमर्थ हैं, से ऋण सहायता प्रदान करवाने के दृष्टिकोण से एक विशेष उद्देश्यीय माध्यम तैयार किया गया है ताकि अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि का ऋण सुलभ हो सके। अधोसंरचना के लिए वित्तीयन करने और संभाव्यता में कमी की पूर्ति करने और लंबी अवधि का ऋण उपलब्ध कराने की ये दो क्षेत्र के वित्तीयन और अधोसंरचना विकास के बीच की दूरी को मिटाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित कर रही है कि निर्माण कार्य की लंबी अवधि की वजह से दीर्घकालिक ऋण की अनुपलब्धता न हो।

8.3.9 अधोसंरचना संबंधी अन्य प्रयास

ऊपर वर्णित प्रयासों के अतिरिक्त ग्रामीण नवीकरण, शहरी नव. ीकरण और उत्तर-पूर्व एवं जम्मू एवं कश्मीर पर इस रिपोर्ट के अनुभागों में अधोसंरचना संबंधी कई अन्य प्रयास किए जा रहे हैं।

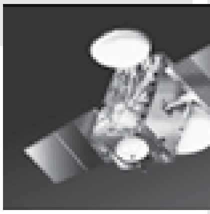

8.4 महंगाई नियंत्रण के लिए कदम

8.4.1 मंहगाई नियंत्रण

यूपीए सरकार का यह प्रयास रहा है कि विकास सतत जारी रखते हुए उपयोगी वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखे और भारतीय उपभोक्ताओं को मंहगाई के विश्वव्यापी रूझान से अप्रभावित रखें। उपयोगी वस्तुओं खाद्यान्न समेत और तेल की कीमतों में वृद्धि, तथा पूंजी आगम के अधिक प्रवाह के बावजूद मंहगाई को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया गया है।

कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तीन गुनी वृद्धि के बावजूद यूपीए सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए केवल सीमित वृद्धि होने दी है। केरोसीन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं।

मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण

9.1 विदेश मामले

यूपीए सरकार ने तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरदृष्टिकोण और परिणाम-उन्मुख विदेश नीति अपनाई है। सरकार ने क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के लिए अनुकूल बाहरी परिवेश के निर्माण के लिए अथक प्रयास किया है ताकि भारत का त्वरित आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सरकार पड़ोसी मुल्कों, विकासशील जगत व गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सहयोगी देशों व सभी प्रमुख शक्तियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध को और सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज वैश्विक पटल पर भारत का कद तेजी से बढ़ा है और इसे एक स्थायी, बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र और तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

9.2 प्रवासी भारतीय

9.2.1 विदेशी नागरिकता

- प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना का विस्तार इस प्रकार किया गया है कि २६ जनवरी, १९५० के बाद भारत से प्रवास कर चुके एवं पवासी भारतीयों को इसकी पात्रता के दायरे में ले लिया गया है। ऐसे विदेशी नागरिकों को आर्थिक, वित्तीय एवं शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ अपवादों को छोड़कर वे सभी सुविधाएं दी गई हैं जो अनिवासी भारतीयों को प्राप्त है। साथ ही, उन्हें जीवनपर्यंत बहुद्देशीय बहु-प्रवेश वीजा दिया जा रहा है और स्थानीय प्राधिकारियों के पास पंजीयन कराने से छूट दी गई है।

9.2.2 विदेशों में रोजगार की सुविधा

- रोजगार के लिए विदेश प्रवास करने वाले लोगों की सहूलियत एवं वहां मुसीबत में पड़े रोजगाररत लोगों की सहायता के लिए विदेशी श्रमिक संसाधन केन्द्र और विदेशी रोजगार प्रोत्साहन परिषद् की स्थापना की गई है। विदेशी श्रमिक संसाधन केन्द्र देशभर के संभावित प्रवासी श्रमिकों को ७ भाषाओं में सूचना प्रदान करता है।

9.2.3 सामाजिक सुरक्षा

- बेल्जियम के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौता किया गया है। इसके तहत लघु अवधि के अंतर्गत पर वहां काम करने गए भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा योगदान के लिए भुगतान करने से

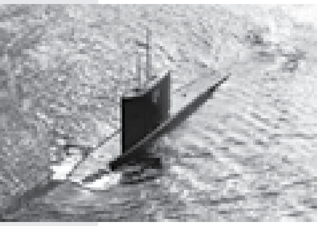

छूट होगी तथा लंबी अवधि के लिए गए लोगों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान से मिलने वाले लाभ भारत वापसी पर उन्हें उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार ने अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी ऐसे समझौतों की दिशा में पहल की है।

9.2.4 पीआईओ विश्वविद्यालय

यूपीए सरकार ने भारतीय मूल के बच्चों एवं लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की नीतिगत रूपरेखा को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस विश्वविद्यालय पर अलगे वर्ष काम शुरु होने की संभावना है।

9.2.5 उत्प्रवास अनापत्ति संबंधी आवश्यकताओं में सुधार

उत्प्रवास अनापत्ति के प्रावधान को रद्द करने से ५ लाख से अधिक ईसीआर धारकों के लिए विदेश यात्रा आसान हो गई है। इन्हें पहले रोजगार छोड़ किसी भी अन्य काम से यात्रा करते समय उत्प्रवास अनापत्ति लेनी पड़ती थी।

9.3 सीमाओं का प्रबंधन

9.3.1 सीमा पर अधोसंरचना

महत्वपूर्ण प्रवेश स्थानों की अधोसंरचना में विकास के लिए यूपीए सरकार ने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार के साथ अपनी सीमाओं पर १३ एकीकृत जांच-चौकियों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है।

आपदा प्रबंधन

10.1 नीतिगत प्रयास एवं तैयारी

10.1.1 वैधानिक एवं सांस्थानिक प्रयास

- मात्र राहत कार्य पर केन्द्रित उपायों की बजाय अब समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपदा की रोकथाम व इसके प्रभावों को कम करने के उपाय किये जा रहे हैं। यूपीए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ लागू कर इसके तहत राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बल की स्थापना का कार्य किया है। कई राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों ने इस अधिनियम के तहत राज्य एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना की है।

10.1.2 दीर्घकालिक पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु सहायता

- सामान्यतया क्षतिग्रस्त अधोसंरचना के दीर्घकालिक पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकारों को अपने नियोजित संसाधनों से खर्च करना पड़ता है। हालांकि परिस्थिति की व्यापकता और सहायता की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने दीर्धाकलिक पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सहायता राशि का प्रावधान किया है जैसा कि वर्ष २००४ में सुनामी, वर्ष २००५ में जम्मू एवं कश्मीर में भूकंप, और वर्ष २००५ में ही नौ राज्यों में भंयकर बाढ़ के दौरान किया गया था। बाढ़ प्रभावित नौं राज्यों को ५,३२३ करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है।

10.1.3 प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में सहायता की शर्तो में संशोधन

- आपदा सहायता के दायरे में भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने और कीटों के भयानक आक्रमण को भी शामिल कर लिया गया है। आपदा सहायता जिन मामलों में दी जाती है और जिन दरों पर दी जाती है उन्हें काफी उदार बनाया गया है ताकि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को अधिक से अधिक सहायता मिल सके। मृतकों के परिवारों, छोटे एवं सीमांत किसानों, और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको अनुग्राह के आधार पर दिए जाने वाले भुगतान की राशि को बढ़ाकर १०० से १५० प्रतिशत तक कर दिया गया है।

10.1.4 बाढ़ प्रबंधन

- यूपीए सरकार ने एक व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। १०वीं योजना में बाढ़ प्रबंधन के लिए ६०० करोड़ रूपये की सहाया को बढ़ाकर ११वीं योजना में ८,००० करोड़ रूपये कर दिया गया है।

10.1.5 आपदा से निपटने की तैयारी

- १६६ सर्वाधिक आपदा प्रभावित जिलों में सामुदायिक आपदा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य है जागरूकता और तैयारी में सक्षमता, तत्परता और विभिन्न स्तरों पर बचाव के माध्यम से आपदाओं से होने वाले जान-माल के खतरों को कम करना।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के व्यापक आधुनिकीकरण का काम शुरु किया जा चुका है। एक अत्याधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली चालू कर दी गई है।
- उपग्रह आधारित आकंड़ों के आधार पर बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के उन्नयन का काम किया जा रहा है।

10.2 तत्काल कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास

10.2.1 सुनामी राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण

- ६,८२२ करोड़ रूपये की लागत से सुनामी पुनर्निर्माण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

10.2.2 आपदा राहत और आपातकालीन सहायता

- विभिन्न राज्यों को पिछले ४ वर्षों में लगभग १६,००० करोड़ रूपये की आपदा राहत और आपातकालीन सहायता प्रदान की गई है।

10.2.3 जम्मू एवं कश्मीर में भूकंप राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण

- राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कुल ५४२ करोड़ रूपये से अधिक की सहायता दी गई है।
- इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त अधोसंरचना के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए ६३६ करोड़ रूपये की सहायता की योजना को स्वीकृति दे दी गई है।

10.3 विस्थापितों एवं दंगा पीड़ितों का पुनर्वास

10.3.1 अपनी जमीन से विस्थापितों का पुनर्वास

- यूपीए सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की नीति तैयार की गई है ताकि विकास परियोजनाओं के कारण अपनी जमीन से विस्थापित लोगों की शिकायतों को दूर किया जा सके। इस नीति के तहत किसी भी प्रकार की परियोजना के कारण अनिच्छा से विस्थापित लोगों की मौलिक जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। यह निति न्यूनतम विस्थापन का लक्ष्य रखती है एवं पर्याप्त, शीघ्र तथा भागीदारी सहित पुनर्वास सुनिश्चित करती है। नीति में समाज के कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है, विस्थापितों के लिए सतत आमदनी सुनिश्चित की गई और नियोजन एवं क्रियान्वयन में पुनर्वास के तत्व का पूरा समावेश किया गया है।
- नीति को वैधानिक आधार देने के लिए संसद में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक, २००७ और भू अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, २००७ पेश किए गए हैं।

१०.३.२ वर्ष १९८४ एवं वर्ष २००२ के दंगा पीड़ितों के लिए

पुनर्वास योजनाएं

- यूपीए सरकार ने वर्ष १९८४ के सिख-विरोधी दंगों के शिकार, और वर्ष २००२ में गोधरा रेल त्रासदी और उसके बाद गुजरात में हुई हिंसा के शिकार लोगों के लिए दो पैकेजों की घोषणा की है। मृत्यु होने, जख्मी होने और आवासीय या बीमा रहित व्यापारिक/औद्योगिक संपत्ति की क्षति होने की दशा में अतिरिक्त अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

अन्य प्रयास

11.1 प्रतिरक्षा

यूपीए सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण ओर देश की प्रतिरक्षा संबंधी तत्परता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। अग्नि ३ मिसाइल को प्रक्षेपण और सशस्त्र बलों में बह्मोस मिसाइल प्रणाली को शामिल करना हमारी प्रतिरक्षा के उन्नयन में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।

11.2 आंतरिक सुरक्षा के उपाय

मोटे तौर पर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। सरकार नक्सली समस्या से पीड़ित राज्यों को आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण के मामले में सहायता प्रदान कर रही है। पुलिस एवं सुरक्षा बलों तथा खुफिया सूचना संग्रह प्रणाली के आधुनिकीकरण पर भी सरकार का पूरा ध्यान है।

11.3 सांप्रदायिक सद्भाव

- मोटे तौर पर सांप्रदायिक स्थिति नियंत्रण में रही है और सांप्रदायिक घटनाओं में बहुत कमी आई है।
- राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का पुनः गठन किया गया है और १२ वर्षों के बाद इसकी बैठक हुई है।
- संसद में सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक पेश किया गया है। इसके उद्देश्य हैं सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम, गवाहों की रक्षा, मामलों का शीघ्र निपटान, राहत के तात्कालिक एवं प्रभावी उपाय, सांप्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों का पुनर्वास एवं मुआवजा, और शीघ्र जांच-पड़ताल तथा सुनवाई।
- शिक्षा के सांप्रदायिक रण की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया गया है।

11.4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- देश में सशक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधार के विकास के उद्देश्य से वर्ष २०१५ तक के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है। इसे प्रभावी करने के लिए ११वीं योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर व्यय तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
- नैनो टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की गई है।

11.5 अंतरक्ष कार्यक्रम

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की उपलब्धि की दिशा में सतत अग्रसर है।

- प्रक्षेपण वाहन क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, स्पेस कैप्स्यूल रिकवरी और सुपरसौनिक कम्बशन प्रौद्योगिकी क्षमताओं को सफलतापूर्वक विकसित और प्रदर्शित किया गया है। भारत ने विदेशी उपग्रहों के व्यावसायिक तौर पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण का काम किया है। भारत की उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं को सुलतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए एक ही प्रक्षेपण वाहन से एक मिशन में १० उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया।

11.6 प्रसारण

- प्रसार भारतीय के कुछ उल्लेखनीय प्रयासों में शामिल हैं • जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक मनोरंजन चैनल की शुरुआत, २४ घंटे का उर्दू चैनल, राष्ट्रीय महत्व की खेल कूद की घटनाओं के प्रसारण का अधिकार प्राप्त करना, स्टूडियों एवं ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण और प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण।
- यूपीए सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्व और द्वीप समूहों में दूरदर्शन और आकाशवाणी सेवाओं को सशक्त बनाया है।
- एफएम रेडियों चैनलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ४ वर्ष पहले सिर्फ २१ निजी चैनल थे जो अप्रैल २००८ के मध्य तक २११ हो गए हैं। शीघ्र ही यह संख्या २६६ होने की संभावना है।

11.7 पर्यटन

- अतुल्य भारत नामक अभियान ने भारत में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। पहली बार भारत में ५० लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है।
- होटलों के लिए भूमि बैंक बनाने की एक नई योजना घोषित की गई है ताकि देश भर में होटलों की कमी को पूरा किया जा सके, विशेष कर राष्ट्रमंडल खेलों के परिप्रेक्ष्य में।

11.8 खेलकूद एवं युवा मामले

- राष्ट्रमंडल खेल २०१० के आयोजन की तैयारियां व्यापक पैमाने पर चल रही हैं।
- यूपीए सरकार ने पंचायत, युवा खेल और क्रीड़ा अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सभी स्थानों पर खेलकूद की मौलिक सुविधा, खेलकूद के सुव्यवस्थित सालाना कार्यक्रम कैलेंडर, और राष्ट्रीय ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम के माध्यम से प्रखंड एवं जिला स्तरों पर खेल और प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है।
- शेष सभी १२३ जिलों में नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

11.9 श्रेण्य भाषाएं

- श्रेण्य भाषाओं की एक नई श्रेणी तैयार की गई है। संस्कृत एवं तमिल को श्रेण्य भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।
- चेन्नई में एक केन्द्रीय श्रेण्य तमिल संस्थान की स्थापना का अनुमोदन किया जा चुका है ताकि तमिल का श्रेण्य भाषा के रूप में विकास हो सके।

11.10 भारतीय डाक

- पिछले ४ वर्षों में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और ८,००० से अधिक डाक घरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। पैसा भेजने की नई प्रणालियों जैसे आईएमओ और फील्ड पोस्टल आर्डर की शुरुआत की गई है। २००८ में ही ई-मनी आर्डर का शुभारंभ होगा। अन्य कई ई-सक्षम सेवाएं लागू की गई हैं तथा कई संभावित हैं।

11.11 अंत्योदय अन्न योजना

- अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार कर अतिरिक्त एक करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया गया है। यह ६७ प्रतिशत की वृद्धि है।

11.12 श्रमिकों को बोनस

- श्रमिकों के लिए बोनस भुगतान की सीमा ३,५०० रूपये से बढ़ाकर १०,००० रूपये प्रतिमाह कर दी गई है।
- सन्निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों को भी बोनस भुगतान के लिए पात्र घोषित कर दिया गया है। ❖

यूपीए सरकार के चार साल पूरा करने पर जारी वार्षिक रिपोर्ट के सारांश

यूपीए गांवों के विकास के लिए कृतसंकल्प

13 जून को गोहाटी, असम, में आयोजित किसान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण

मुझे खुशी है कि आज मैं इस किसान रैली में आपके बीच हूं।

हमारे किसान भाई हमारे देश की शान हैं। असम में किसानों की मेहनत, ईमानदारी और बहादुरी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फुलागुड़ी और पतुरुघाट के किसानों ने १८६१ और १८९४ का आंदोलन अंग्रेजों के जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। इसमें हिंदू और मुसलमान - सभी भाइयों की तरह दिल और दिमाग की एकता के साथ शामिल थे, अपना लहू बहाया, अपने प्राण न्यौछावर किए। यही हमारे देश की पहचान है। मैं उन सभी शहीद किसानों की स्मृति को प्रणाम करती हूं।

इसी के साथ मैं आपके बीच गर्व के साथ यह भी कहना चाहती हूं कि असम के लोगों की देशभक्ति, त्याग और बलिदान का भी अपना एक अलग इतिहास है। कहा जाता है कि हमारे प्रथम स्वाधीनता आंदोलन से पहले ही असम के लोगों ने १८२७ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। उसके बाद आजादी के दिन तक यह महान पंरपरा चलती रही। मैं सभी स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि देती हूं।

जहां असम के लोग जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, वहीं मन से वे शांति-प्रिय हैं। मैं भी जानती हूं कि हर समस्या को शांति के वातावरण में बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। जब-जब यहां अशांति और उथल-पुथल का माहौल रहा, प्रदेश की प्रगति और विकास में बाधा आयी है। इसीलिए जब यहां अखिल असम छात्र संघ का आंदोलन तेजी पर था तो राजीव जी ने बातचीत की पहल की और १९८५ में शांति और खुशहाली के लिए असम समझौता किया। हम असम समझौते का पालन करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है - चाहे सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे सही भारतीय नागरिक को नाजायज रूप से परेशान करने का मामला हो। इसके अलावा चाहे इस समझौते से जुड़ी हुई विकास की योजनाएं हों - जैसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी उच्च शिक्षा संस्थाएं हों, गैस क्रैकर परियोजना हो, मुझे खुशी है कि हमारी यूपीए सरकार इन सभी पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक असम के विकास और प्रगति पर खास ध्यान दे रही है।

असम के सबसे ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। यहां की आर्थिक स्थिति, किसानों, बुनकरों और दस्तकारों की दशा पर निर्भर है। इसीलिए हमारी यूपीए की केन्द्र सरकार डा. मनमोहन सिंह जी के नतृत्व में सभी योजनाएं यहां के साथ-साथ देश और दूसरे प्रदेशों के आम आदमी के लिए खासतौर से बनाए हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं और खेती का काम करते हैं। इसीलिए केन्द्र सरकार ने छोटे और मध्यम किसानों की मुश्किलों को ध्यान में रखकर ७०,००० करोड़ रूपये कर्ज माफ करने जैसा कदम उठाया है। ऐसा काम किसी गैर-कांग्रेसी सरकार ने कभी नहीं किया। इतना ही नहीं, धान का एमएसपी बोनस के साथ अभी तक ७४५ रूपये था, जिसे अब बढ़ाकर ८५० रूपये कर दिया गया है। चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए करीब छः सौ करोड़ रूपये का एक टी-कोष मंजूर किया है। दलित, आदिवासी और पिछड़े भाई-बहनों के लिए अलग से पैसा दिया गया है।

यूपीए सरकार का भारत निर्माण जैसा कार्यक्रम गांवों में विकास का बुनियादी ढांचा तैयार करने के इरादे से बना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी योजना गांवों से गरीबी हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, एक बड़ी शुरुआत है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और नयी कृषि नीति से सिंचाई की सुविधाएं, मछली पालन और डेयरी को बढ़ावा देने से किसानों और गांवों के लोगों के जीवन में सुधार होगा।

यहां की हमारी राज्य सरकार भी तरूण गोगोई जी के नेतृत्व में किसान, बुनकर भाइयों और गांवों के दस्तकारों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कदम उठा रही है। आपके यहां तेरह जिले ऐसे हैं, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या काफी है। इन इलाकों के लिए केन्द्र सरकार ने अलग से कई विकास योजनाएं शुरु की हैं। आपके यहां बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने जो टॉस्क फोर्स बनाया था, उसके सुझाव पर कार्रवाई हो रही है।

मुझे इस बात की खासतौर से खुशी है कि हमारी बहनों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज असम में डेढ़ लाख के आस-पास जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, उसमें ८० प्रतिशत के करीब मेरी बहनें हैं। इसके अलावा हमारी प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शिक्षा और गरीब परिवारों के लिए जो अनेक योजनाएं शुरु की हैं, उनका भी अच्छा असर दिखायी पड़ने लगा है। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहती हूं कि हमारा देश और हमारे प्रदेश सही मायने में तभी आगे बढ़ेंगे, जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी।

आजकल हम सभी की एक चिंता है, मंहगाई की। लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं, जिनका सामना करना ही पड़ता है। आप सोचिए कि आज तेल

उत्पादक देशों में भी तेल और बाकी सामान की कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं। हमारे पड़ोसी देशों में भी हमारे यहां से ज्यादा बढ़ गयी हैं। फिर भी हमारी सरकार ने उसे कम रखने की हर संभव कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से और अन्य कोई विकल्प न रहने पर हमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। लेकिन आज भी इसका ज्यादा बोझा केन्द्र सरकार खुद उठा रही है। मिट्टी के तेल के दाम सरकार ने तब भी नहीं बढ़ाए। जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, उन्होंने कर में छूट देकर कीमतों में राहत देने की कोशिश की है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने आपके मुख्यमंत्री जी को कर पर छूट देने को कहा, तो उन्होंने उसी समय एकदम मान लिया। एक बात आप सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तेल की कीमत भाजपा की राजग सरकार के जमाने में तीस से चालीस डालर प्रति बैरल थी, वह आज हमें एक सौ तीस से एक सौ चालीस डालर प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है। आज मंहगाई पर हमारे विरोधी जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपने अतीत में झांकने की आवश्यकता है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अन्य चीजों की मंहगाई भी बढ़ गयी है। ऐसी परिस्थिति को देखकर, जब हम सबको, खासकर गरीबों को, हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मैं समझती हूं कि हम सभी को परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझना चाहिए।

हमारी केन्द्र और राज्य सरकारें जो कुछ भी कर रही हैं, वह सभी वर्गों के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, खासतौर से युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कर रही हैं। नयी पीढ़ी से ही हमेशा देश का भी भविष्य बनता है। असम के युवाओं में भी खूब प्रतिभा और योग्यता है। हम उन्हें और अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा, सुविधाएं देकर दुनिया भर में और ज्यादा चमकने का अवसर दे सकते हैं। हम उन्हें और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी शुभकामना असम के एक-एक युवा के साथ हैं, एक-एक नागरिक के साथ हैं। उनके संघर्ष को हम अपना संघर्ष मानते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा में आने के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूं। जय हिंद। ❖

शोक प्रस्ताव

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जयपुर में हाल में आतंकवादी हमलों से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है। पार्टी इन हमलों की निन्दा करती है तथा सभी तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दुहराती है। यह देश के उन लोगों को बधाई देती है जिन्होंने बार-बार पंथनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया है और भारी उकसावे की हालत में भी सांप्रदायिक सद्भाव को भंग नहीं होने दिया। देश में ऐसी राजनीतिक शक्तिया हैं जो हर आतंकवादी हमले के समय हमारे समाज में ध्रुवीकरण करना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी शक्तियों से पूरी दृढता के साथ राजनीतिक रूप से मुकाबला करेगी।

कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी का प्रस्ताव

कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी की ३१ मई, २००८ को हुई बैठक कर्नाटक सहित हाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावी हार पर गौर करती है। कांग्रेस ने अपने लम्बे इतिहास के दौरान सफलताओं तथा विफलताओं की स्थिति का सामना किया है, परन्तु इसने कभी भी अपने काम-काज पर निराशा और निष्क्रियता की भावना को हावी नहीं होने दिया। कांग्रेस में अस्थाई चुनावी हार से सबक लेने तथा उभरती चुनौतियों का समाना करने की क्षमता है।

राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। यह बात साफ है कि सिर्फ चुनावी प्रचारों से ही जीत नहीं होती। व्यापक चुनाव प्रचार को वोट में बदलनें के लिए लोगों से पूरे साल लगातार संपर्क बनाए रखना, उनकी उम्मीदों तथा आकांक्षाओं तथा उनकी दैनिक चिन्ताओं को समझना भी जरूरी है। यह काम एक ऐसे संगठन के बल पर ही संभव है जो बुनियादी रूप से ठोस तथा जागृत हो और जिसने जिम्मेवारी और जवाबदेही के बीच की साफ लकीर तय कर रखी हो। इस मकसद को पूरा करने के लिए कांग्रेस को अपने सारे सदस्यों तथा आम लोगों से जीवंत सम्पर्क कायम करना होगा।

कांग्रेस को गर्व करने के अनेक आधार हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं तथा उपलब्धियां हासिल की है। खेती, ग्रामीण रोजगार, शहरी विकास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और स्वास्थ्य को अपूर्व रूप से प्रोत्साहन दिया गया। सभी कांग्रेस कर्मियों - पुरूषों तथा महिलाओं को अवश्य ही देश के लोगों के बीच यूपीए सरकार की पहलों तथा उसके कार्यों का पूरा प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

कांग्रेस का सभी तरह की साम्प्रदायिक, विघटनकारी और कट्टरपंथी शक्तियों से लड़ने का इतिहास है। जबकि यह बात सही है कि भाजपा कुछ राज्यों में चुनाव जीत गई है, कांग्रेस का ख्याल है कि उसका उभार समाज के मूल ताने-बाने और हमारे पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्रवादी लोकोपचार संबंधी चरित्र के लिए हानिकर है। कांग्रेस सैध्दान्तिक तथा चुनावी तरीके से भाजपा का मुकाबला करती रहेगी। भारत के प्रति भाजपा की सोच तथा कांग्रेस की सोच में मौलिक अंतर है। हमारी सोच जोड़ती है, भाजपा की सोच तोड़ती है।

कांग्रेस विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं लड़खड़ाई है। कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी यह संकल्प करती है कि वह अपने मूल सिद्धान्तों को छोड़े बिना राष्ट्रहित में काम करने के लिए पार्टी को सक्रिय बनाएगी। कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी सभी कांग्रेसकर्मियों-पुरूषों तथा महिलाओं - से आग्रह करती है कि वे एक संयुक्त, एकजुट तथा प्रेरित टीम के रूप में काम करें ताकि हम आगामी चुनाव प्रचारों में सफल रहें। ❖

राजीव को श्रद्धांजलि

राजीव की प्रतिमा का अनावरण

पटनाः कांग्रेस कर्मियों ने यहां बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय-सदाकत आश्रम-में राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नगर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजीव गांधी की संगमर्मर से निर्मित आवक्ष प्रतिमा सदाकत आश्रम परिसर में लगाई गई है। इसका अनावरण पूर्व केन्द्रीय मंत्री, स्वाधीनता सेनानी तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही ने किया।

कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सदानन्द सिंह, विधान सभा में विपक्ष के नेता डा० महाचन्द्र प्रसाद सिंह तथा पार्टी के पदाधिकारी सहित अनेक कांग्रेसकर्मी मौजूद थे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा तथा एक गोष्ठी भी आयोजित की गई। गोष्ठी का विषय था - राजीव का संदेश : निजहित से ज्यादा देश को प्राथमिकता"।

करनालः हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा राजीव गांधी युवा सेना ने यहां

राजीव गांधी की पुण्य तिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव श्री कंवल भसीन के नेतृत्व में कांग्रेसकर्मियों ने राजीवजी के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धाजंलि दी।

श्रद्धांजलि देनेवालों में रमेश आजाद, ओम प्रकाश सचदेव, डा. फतहचन्द, सतीश सागर, सुरेश मदान, सोमपाल, नरेन्द्र जोगा, पृथ्वी, गुलशन कुमार, जीत सिंह, सुरेन्द्र उप्पाली, संजीव, नली, राजवीर सिंह पाल, सतपाल सांभली, शशिकान्त शर्मा, पंकज, सुशील कुमार, रामनिवास, हरपाल गौड़, किशनलाल, चरणजीत शर्मा, सतपाल, वेद त्यागी तथा दूसरे लोग भी शामिल थे।

जमशेदपुरः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री राजेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। उनकी १७वीं पुण्यतिथि के मौके पर २१ मई को आयोजित लेखन प्रतियोगिता में करीब ५०० स्कूली बच्चों के स्कूली बैग, पेंसिल तथा टी-शर्ट बांटे गए। श्री शुक्ला ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव कराकर ही हम राजीव गांधी को सही श्रद्धांजलि दे सकते हैं। राजीव गांधी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने पंचायती राज के माध्यम से गांव के लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाया। पंचायती राज उनकी सोच का ही परिणाम है।

राजीव ज्योति

बेंगलुरुः राजीव गांधी सद्भावना ज्योति उनकी १७वीं पुण्यतिथि के मौके पर २१ मई को श्री पेरुम्बुदूर पहुंची। यह इस ज्योति को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह तथा केन्द्रीय मंत्री श्री बी. नारायण स्वामी ने १७ मई को रवाना किया था। यह ज्योति कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम विभाग के संयोजक श्री एस.एस. प्रकाशम के नेतृत्व में वहां पहुंची। ज्योति यात्रा मैसूर, कालीकट, कन्याकुमारी, मदुरै, पुडूचेरी तथा चेन्नई होते हुए श्री पेरुम्बुदूर पहुंची। इस ज्योति को मंत्री श्री के.एच. मणियप्पा ने ग्रहण किया। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री के.बी. कृष्णमूर्ति, तमिलनाडू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री एम. कृष्णस्वामी तथा श्री जे.एम. हारून भी मौजूद थे।

मुंबईः पूर्वोत्तर मुंबई जिला कांग्रेस ने यहां २१ मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। श्री गुरुदास कामत, सांसद, की पहल पर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री अनिल शर्मा

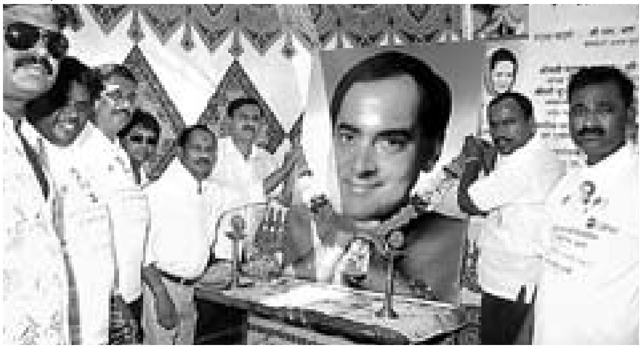

ने २४ मई को मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता तथा नगर पार्षद भी मौजूद थे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की देखरेख में नेत्र, दांत, आम बीमारी, मधुमेह के रोगियों तथा उनके रक्त ग्रुप की जांच की गई। कुल करीब २००० रोगियों की जांच की गई तथा ५०० चश्मे बांटे गए।

राजीव प्रतिमा पुरस्कार

भुवनेश्वरः राजीव गांधी स्टडी सर्किल तथा राजीव गांधी स्टुडेंट्स फोरम के

कांग्रेस कर्मियों तथा पदाधिकारियों ने जयदेव भवन में २१ मई को आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल

श्री मुरलीधर चन्द्रकान्त भंडारे के नेतृत्व में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में राज्यपाल ने "राजीव गांधी प्रतिभा पुरस्कार" बांटा।

पुडूचेरी: पुडूचेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री ए.वी. सुब्रमणियम के नेतृत्व में कांग्रेस कर्मियों ने २१ मई को यहां राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री नारायण स्वामी भी मौजूद थे। इस दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुडूचेरी से श्री पेरूम्बुदूर तक मशाल यात्रा भी निकाली।

त्रिची (तमिलनाडू): त्रिची जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की १७वीं पुण्यतिथि के मोके पर २१ मई को शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का नेतृत्व तमिलनाडू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री बी. बाल सुब्रमणियन ने किया। उन्होंने श्री राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस तिथि को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने आतंकवाद से मुकाबले का संकल्प लिया। करीब १००० लोगों को भोजन भी कराया गया।

संकल्प दिवस

खुटहन (जौनपुर): कांग्रेसकर्मियों ने दौलतपुर में २१ मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि संकल्प दिवस के रूप में मनाई। कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री इन्द्रमणि दूबे के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

श्री दूबे ने राजीव गांधी की भूमिका की चर्चा की और कहा कि उनके द्वारा लागू सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ अब हमें मिल रहे हैं और भारत के लोग इस क्षेत्र में न सिर्फ अपने देश, बल्कि दुनिया भर में अच्छा नाम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से उनके बताए रास्ते पर चलने का आग्रह किया।

संत कबीर नगर (उ.प्र.): कांग्रेसकर्मियों ने यहां २१ मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की १७वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर जिले के हरिहर स्थित नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व श्री अखंड बहादुर पाल ने किया। कार्यक्रम में श्री तीरथ प्रसाद, श्री फोगू, श्री राम आशीष गुप्ता, श्री निसार अहमद, श्री राणे सिंह, श्री रू

पल गौड़, श्री अख्तर हुसैन, श्री सूर्यलाल गुप्ता, श्री अमीर, श्री दगानू, श्री सुनील, श्री नेबूलाल गुप्ता तथा अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया।

राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि

इलाहाबाद: भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को शहर तथा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यर्ताओं ने उनके १८वें शहादत दिवस पर आयोजित आतंकवाद विरोध दिवस पर २१ मई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया और आतंकवाद के विरूद्ध से लड़ाई का संकल्प लिया। प्रातः दिवंगत नेता के पैतृक आवास आनंद भवन पहुंचकर बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए महापौर तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष चौ. जितेन्द्र नाथ सिंह ने कहा कि आज हमें उन ताकतों से आतंकवाद की चुनौती मिल रही है जो देश में शांति एवं विकास में रूकावट तथा आर्थिक सुधार को रोकना चाहती है। विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने लोगों का आह्वान किया कि वे इसके प्रति चौकस रहें और मुल्क की एकता के लिए काम करें जिसके लिए

इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव फुजैल हाशमी ने आतंकवाद एवं दहशतगर्दी के खिलाफ युवा पीढ़ी से संघर्ष करने की अपील की। श्रद्धांजलि सभा का संचालन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री किशोर वार्ष्णेय ने किया। उन्होंने देश में बढ़ते आतंकवाद की निंदा करते हुए धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत करने पर बल दिया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव फुजैल हाशमी, पी.सी.सी. सदस्य किशोर वार्ष्णेय, जिलाध्यक्ष अमर नाथ मिश्रा, आर.एन. राकेश, प्रो. राम किशोर शास्त्री, एच.एन. मेहरोत्रा, प्रो. यमुना पांडेय, संजय तिवारी, सहित अनेक लोग शामिल थे।

पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि

इलाहाबादः आधुनिक भारत के निर्माता तथा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को २७ मई को उनकी ४४वीं पुण्यतिथि के मौके पर शहर तथा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर स्मरण किया। प्रातः उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने नेहरू के पैतृक आवास आनंद भवन जाकर राष्ट्रनेता के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए डा. रीता जोशी ने कहा कि पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्ष भारत की आधारशिला थे। वे विश्व शांति के प्रतीक थे, जिन्होंने देश को आर्थिक मजबूती प्रदान की थी। डा. जोशी ने कहा कि पंडित नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा पंचशील सिद्धांत के प्रणेता थे।

कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी ने पंडित नेहरू की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि आज मुल्क खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत है तो वह पंडित नेहरू की देन है। श्रद्धांजलि सभा का संचालन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री किशोर वार्ष्णेय ने किया।

पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले प्रमुख लोगों में महापौर चौ. जितेन्द्र नाथ सिंह, विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, रामपूजन पटेल, फुजैल हाशमी, शेखर बहुगुणा, राजेन्द्र त्रिपाठी, आर.एन. राकेश, विनीता बहुगुणा, सहित अनेक लोग शामिल थे। बाद में कांग्रेसजनों ने बालसन चौराहा स्थित

पंडित नेहरू की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें याद किया।

कार्यशाला

रायपुर (छत्तीसगढ़)ः छत्तीसगढ़ की एनएसयूआई शाखा ने यहां २१ मई को सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला आयोजित कर श्री राजीव गांधी की १७वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

राज्य एनएसयूआई अध्यक्ष श्री विकास उपाध्याय की पहल पर स्पेक्ट्रम हॉल में कंप्यूटर पर आयोजित इस कार्यशाला में करीब २०० लड़के एवं लड़कियों

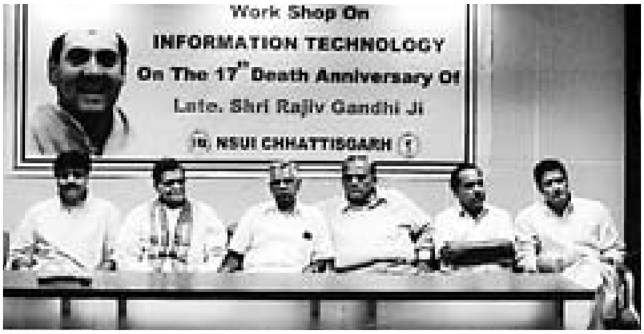

ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

हिस्सा लेनेवालों में प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अनिल पुसादकर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री इन्दरचन्द घाड़ीवाल, प्रदेश सचिव श्री संजय पाठक, विपक्ष के नेता श्री कुलदीप जुनेजा, श्री प्रमोद दूबे, श्री राजेश अग्रवाल, श्री सुधीर शर्मा, श्री जगदीश आहूजा, श्री मदन तलेदा, एनएसयूआई के राज्य प्रवक्ता श्री संदीप तिवारी तथा अन्य लोग शामिल थे।

मुंबईः मुंबई युवा कांग्रेस (ब्लॉक ७६) ने यहां २१ मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी १७वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। युवा कांग्रेस ने इसे आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया।

ब्लॉक अध्यक्ष डा. त्रिलोकी मिश्र ने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आतं. कवाद का पुतला भी जलाया। इस मौके पर ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष सईद अयूब, मुंबई प्रदेश कांग्रेस के सचिव श्री राम गोविन्द यादव तथा श्री रायमणि

भी मौजूद थे। अन्य मौजूद लोगों में जिला प्रतिनिधि श्री विजय तिवारी, डा. राकेश द्विवेदी, श्री गणेश शिन्दे, श्री महेश लिजा, श्री प्रदीप वर्मा, श्री अमीन शेख, माधुरी सिंह, कांति शाह, अमन प्रीत तथा अन्य शामिल थे।

पोलियो जागृति रैली

मलाड (मुंबई)ः उत्तर मुंबई कांग्रेस कमेटी ने पोलियो ड्राप की उपयोगिता के बारे में जागृति पैदा करने के लिए २७ अप्रैल को जनजागृति रैली निक.

ाली। इसका नेतृत्व कमेटी के संगठक सचिव डा. नसीम अहमद ने किया। रैली में कमेटी के उपाध्यक्ष श्री अकील वली मोहम्मद के अलावा ब्लॉक अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महिला सेल तथा अल्पसंख्यक सेल के प्रभारियों ने भी हिस्सा लिया।

मुफ्त खाद्यान्न वितरित

मुंबईः महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गरीबों के बीच मुफ्त खाद्यान्न बंटवाया। खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम युवा एवं खेल प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डा. मनोज दूबे ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिदोंसी थाने के प्रभारी

किशन सोलंकी, श्री सदाराम बाबले, श्री दीपक पनेरी, श्री दिदासा जयेश शाह, श्री कमला प्रसाद यादव, श्री नागेन्द्र पांडे, श्री सुदामा सावंत, श्री जदीश भावसान, श्री राजू व्यास, श्री नंदलाल यादव, श्री समीर दावड़ा, श्री नीलेश जाधव, श्री पंचम लाल वर्मा तथा अन्य लोगों ने मदद की।

पिछड़ा वर्ग के साथ विचार मंथन

भोपालः मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश पचौरी ने पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री के.सी. लेंका एवं श्री रामभुवन सिंह पटेल, सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, पिछड़ा वर्ग विभाग, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रभारी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा के साथ प्रदेश में पिछड़ा वर्गों से संबंधित वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आगामी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया। उनका सुझाव था कि मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के सभी वरिष्ठ नेताओं को अपने-अपने विचार पार्टी हित में प्रकट करना चाहिए।

श्री के.सी. लेंका ने अपने भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को पिछड़े वर्गों का मसीहा बताया तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश पचौरी के नेतृत्व को पिछड़े वर्ग के सभी भाइयों एवं बहनों से पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया। श्री पचौरी ने अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में अपने वाली, संपूर्ण जातियों को उचित स्थान देने पर जोर डाला।

श्री राम भुवन सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में श्री सुरेश पचौरी को पिछड़ा वर्ग की ओर से पूर्ण समर्थन देने तथा उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अगली सरकार बनाने का संकल्प लिया।

बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि

जबलपुरः अखिल भारतीय आदिवासी शिवरी महासंघ के पदाधिकारियों तथा

कांग्रेसकर्मियों ने अ० भा० कांग्रेस कमेटी की सचिव सुश्री कौशल्या गोटिया के नेतृत्व में महान् क्रांतिकारी श्री बिरसा मुंडा को उनके शहीदी दिवस पर ६ जून को श्रद्धांजलि दी। सुश्री गोटिया ने इस मौके पर कहा कि आठ साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक लाख रूपए के नकद पुरस्कार की योजना बनाई थी, परन्तु यह पुरस्कार आज तक किसी को नहीं मिला।

धरना और रैली

टीकमगढ़ः जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव श्री पवन घुवारा के नेतृत्व में कांग्रेस कर्मियों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस

निकाला तथा धरना दिया। वे वायदों पर अमल न करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

कुशासन के खिलाफ प्रदर्शन

सम्बलपुर (उड़ीसा)ः उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार के कुशासन

के खिलाफ करीब पांच हजार कांग्रेसजनों ने १६ मई को यहां प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान करीब ३,१५३ कांग्रेसजनों ने अपनी गिरफ्तारी कराई।

कांग्रेसजनों का नेतृत्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक श्री राजेश कुमार शुक्ला, सम्बलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश्वर मिश्र, पूर्व सांसद श्री वल्लभ पाणिग्रही, उड़ीसा प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रोहित पुजारी तथा श्री काल्टू चक्रवर्ती कर रहे थे।

श्री शुक्ला ने कहा कि उड़ीसा प्रशासन में भारी घपला हो रहा है। राज्य प्रशासन केन्द्रीय परियोजनाओं को राज्य सरकार की परियोजना होने के दावा कर रहा है। कांग्रेसकर्मी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने आज यहां प्रदर्शन किया। श्री शुक्ला ने पार्टी जनों से आग्रह किया कि वे यूपीए सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में आमजन को जानकारी दें। साथ ही उन्हें यह बताएं कि राज्य सरकार की क्या-क्या जन-विरोधी नीतियां हैं।

दूसरे वक्ताओं में श्री वल्लभ पाणिग्रही, श्री रोहित पुजारी, श्री सुरेश्वर मिश्र, श्री प्रमोद कुमार रथ, श्री शोभाराम प्रधान, श्री अभिमन्यु कुमार, श्री अशरफ खां, सलीला पांडा, श्रीमती सदामणि नन्दा, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री जयशंकर मिश्र, श्री बादल दानी, श्री सत्येन्द्र बोईदर, श्री नरेन्द्र मिश्र, प्रिया वन्दूका, श्री देवाशीष दास, कविता पुरोहित, काल्टू चक्रवर्ती तथा अन्य लोग शामिल थे।

राजीव के आदर्शों पर अमल ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि

बागपतः कांग्रेसकर्मियों ने यहां २१ मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की १७वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुरुषों एवं मि. हलाओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया तथा दो मिनट मौन रहकर उनको श्रद्धांजलि दी। श्री बालेश्वर शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती लता चौधरी के नेतृत्व में माता कालोनी में महिलाओं ने श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देनेवालों में राजकुमार, ओम प्रकाश कौशल, जगदीश, शरीफ, संजीदा, पप्पू, संगीता, राजेश, सिमला, पार्वती तथा अन्य लोग शामिल थे। लता चौधरी ने लोगों से राजीवजी के आदर्शों को ग्रहण करने तथा उनकी नीतियों का प्रचार कर देश को मजबूत बनाने का आग्रह किया।

इससे पहले लता चौधी के नेतृत्व में आयोजित रैली में स्थानीय समस्याओं की मायावती सरकार द्वारा अनदेखी के विरोध में एक रैली आयोजित की गई। रैली नगर भ्रमण के बाद तहसील कार्यालय के पास जाकर समाप्त हो गई जहां एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। रैली के कारण दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर यातायात ठप रहा। प्रतिनिधिमंडल ने सुश्री मायावती द्वारा श्री राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने का भी विरोध किया।

रैली में डा. विवेक पवार, श्री सुरेश राणा, श्री शिवकुमार कटारिया, अंजू शर्मा, बबिता, सुमित्रा, सुमन, शिखा देवी, सुरेश बाला, उर्मिला, उमरेश, ओंकारी, रवि प्रकाश, राजेश्वरी एवं फातिमा ने भी हिस्सा लिया।

धन्यवाद रैली

अंगुल (उड़ीसा): नालको को नवरत्न का दर्जा प्रदान किए जाने के उपलक्ष में यहां १३ मई को धन्यवाद रैली आयोजित की गई। रैली का आयोजन इंटक की उड़ीसा शाखा ने किया था।

सांसद तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राहुल गांधी ने राज्य एवं नालको फैक्टरी का दौरा किया तथा इसे नवरत्न का दर्जा संबंधी प्रमाणपत्र सौंपा। अखिल भारीतय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा इंटक की उड़ीसा शाखा के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र खूंटिया, सांसद ने रैली में श्री राहुल गांधी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। रैली में नालको के हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

श्री राहुल गांधी ने स्मृति चिन्ह ग्रहण करते हुए कहा, "मेरे प्रयास से नहीं, बल्कि नालको के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को मान्यता प्रदान करते हुए इस कंपनी को यह दर्जा प्रदान किया गया है। श्री गांधी ने नालको का कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि नालको के निजीकरण का सवाल ही नहीं उठता है।"

शहरी विकास राज्य मंत्री तथा उड़ीसा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी श्री अजय माकन ने इस मौके पर कहा कि नालको कांग्रेस पार्टी के सपने का साकार रूप है। नालको परियोजना को श्रीमती इंदिरा गांधी ने चालू किया था तथा श्री राजीव गांधी ने उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। रैली में उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जयदेव जेना, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री के.पी. सिंहदेव, पूर्व सांसद श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही और श्री खूंटिया ने भी भाषण दिए।

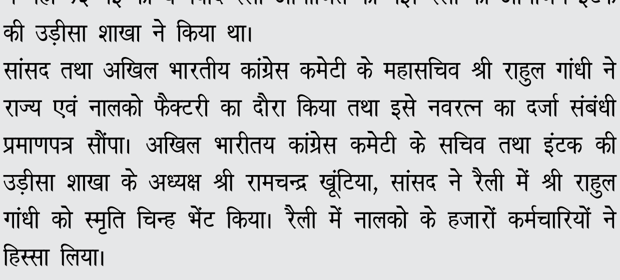

श्रद्धांजलि

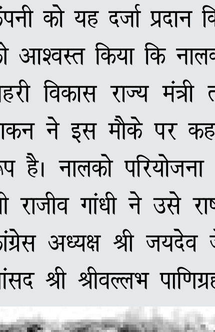

श्री संजय गांधी को उनकी २८वीं पुण्यतिथि के मौके पर २३ जून को राष्ट्र की श्रद्धांजलि

राजीव गांधी ग्रामीण क्रिकेट

अमेठीः राजीव गांधी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच यहां १ जून को मुसाफिर खाना स्थित अंबेडकर स्टेडियम में खेला गया। मैच संग्रामपुर टीम ने जीता। उसने तिलोही टीम को हराया। नीलेश सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। टूर्नामेंट में कुल १८५७ टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों के ज्यादातर सदस्य दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के थे।

क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर ने ट्रॉफी तथा ३ लाख रूपये के चेक बांटे जबकि श्रीमती प्रियंका तथा श्री राबर्ट वडरा ने रनर्स-अप ट्रॉफी प्रदान की।

इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राहुल गांधी, सांसद, तथा क्रिकेटर श्री आर.पी. सिंह एवं श्री पंकज सिंह भी मौजूद थे। फाइनल मैच के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था।

महिला कांग्रेस रिपोर्ट

पूरे मई महीने महिला कांग्रेस की देशव्यापी गतिविधियां जारी रहीं। एक मई को श्रम दिवस था। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती आभा चौधरी ने जरूरतमंदों तथा विधवाओं के बीच साड़ियां तथा सिलाई मशीनें जबकि उनके बच्चों में स्टेशनरी बांटी। कार्यक्रम शकूरपुर बस्ती में आयोजित किया गया था। इस भारी सफल कार्यक्रम में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष तथा दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती कृष्णा गहलावत भी मौजूद थीं।

६ मई को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की महिलाकर्मियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से मिला तथा महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देनेवाला विधेयक संसद में पेश किए जाने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष डा. प्रभा ठाकुर ने किया तथा मिठाई भी बांटी। देशभर में महिला कांग्रेस की शाखाओं ने खुशी मनाई, मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला एवं बाल किवास मंत्री, भारत सरकर, को एक ज्ञापन देकर एसिड डाले जाने से प्रभावित महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास का आग्रह किया तथा केन्द्र एवं राज्यों में "एसिड एटैक विक्टिम्स असिस्टेंस बोर्ड" के गठन का सुझाव दिया।

मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती जैनेट डिसूजा ने १२ मई, २००८ को राज्य महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों तथा ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की। बैठक में मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, स्थानीय सांसद, महिला विधायक, श्रीमती अण्णेई शेखर तथा श्रीमती अल्का देसाई, विधान पार्षद तथा पूर्व सांसद श्रीमती सुधा जोशी भी मौजूद थीं। इसके बाद संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। १३ मई को कर्नाटक प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रानी सतीश अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मंगलोर गई जहां आयोजित जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी

ने भाषण दिया। १४ मई को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने गुलबर्गा के कमालपुर विधान सभा क्षेत्र में महिला उम्मीदवार श्रीमती चन्द्रिका परमेश्वरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। श्रीमीत रानी सतीश, डा. टी. कल्पना देवी, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, तथा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सचिव श्रीमती मंजुला नायडू भी सभी सभाओं में मौजूद थीं।

जयपुर के बम-विस्फोटों से प्रभावित इलाकों के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ गई टीम में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थीं। बाद में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष डा. प्रभा ठाकुर के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा तथा राज्य के दूसरे पदाधिकारियों ने बम विस्फोट से प्रभावित लोगों को अस्पताल में जाकर देखा तथा उन्हें फल और खाने की अन्य चीजें दी। उसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से बात की। तथा महिला कांग्रेस की स्थानीय शाखा को निर्देश दिया कि २१ मई तक लगातार हर दिन अस्पताल जाकर इन रोगियों से मिलती रहें।

१६ मई, २००८ को टाउन हाल, दिल्ली, में दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती आभा चौधरी ने भाजपा-नीत दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सीलिंग तथा निर्माण ध्वस्त करने के अभियान के खिलाफ डा. प्रभा ठाकुर के नेतृत्व में धरना आयोजित किया। धरना के मुद्दों में विभिन्न मुहल्लों में सफाई की कमी तथा महिला कांग्रेसकर्मियों को वृद्धावस्था पेंशन देने में अनियमितता बरतने के मुद्दे भी शामिल थे।

आंध्र प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती गंगा भवानी ने १७ मई को विकाराबाद में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए संवाददाता सम्मेलन तथा मण्णेगुडा में चुनाव सभा आयोजित किया। १८ मई को डा. प्रभा ठाकुर ने पूर्वाह्न ११ बजे गांधी भवन में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा कार्यकत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की।

१६ मई, २००८ को छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती वाणी राव ने रायपुर में राज्य स्तरीय महिला कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष डा. प्रभा ठाकुर ने की। सम्मेलन में राज्य के पदाधिकारी, जिला, नगर तथा ब्लॉक अध्यक्ष और करीब २५०० महिला कांग्रेसकर्मी मौजूद थीं।

इंदौर में २० मई को इंदौर मंडल का महिला कांग्रेस सम्मेलन तथा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस मंडल में इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बदवानी, खांडवा और राहनपुर जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने इसका आयोजन किया था। सम्मेलन में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष डा. प्रभा ठाकुर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री सुरेश पचौरी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री नारायण स्वामी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, तथा अन्य स्थानीय नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव डा. शोभना शाह, जो मध्य प्रदेश की प्रभारी भी हैं, सहित करीब १०,००० महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया।

देशभर में महिला कांग्रेस की शाखाओं ने प्रिय नेता राजीव गांधी को २१ मई, २००८ को कई कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। इन कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर तथा अनाथों के बीच फल वितरण शामिल हैं। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती गोपाल कुंवर दूबे ने इस दिवस को 'आतंकवाद विरोधी दिवस' के रूप में मनाया।

दिल्ली में २४ अकबर रोड पर स्वास्थ्य जांच शिविर तथा नेत्र जांच शिविर लगाए गए। इसका आयोजन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती आभा चौधरी के सहयोग से किया। दिल्ली और हरियाणा की जरूरतमंद महिलाओं को निश्शुल्क आंख की दवा तथा चश्मे दिए गए। श्री मोतीलाल वोरा, श्रीमती मोहसिना किदवई तथा डा. प्रभा ठाकुर ने शिविर का उद्घाटन किया। श्रीमती कृष्णा गहलावत, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, तथा दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रभारी अन्य पदाधिकारियों के साथ मौजूद थीं।

– शोभना शाह, महासचिव, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस

पूर्व सैनिकों द्वारा सांप्रदायिकता एवं जातिवाद की निंदा

जिन राज्यों में इस साल नवंबर में चुनाव होनेवाले हैं उनमें राजस्थान का पूर्व सैनिकों की नजर में खास महत्व है। इस राज्य में उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा पूर्व सैनिकों की सर्वाधिक आबादी हैं, इसलिए पूर्व सैनिक विभाग ने इस माह इस राज्य के पूर्व सैनिक बहुल नागौर से अपनी पार्टी का चुनाव अभियान शुरु किया।

नागौर के बीचोंबीच स्थित कुचमान तालुक में पूर्व सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन ८ जून, २००८ को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग की देखरेख में नागौर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग ने किया था।

सम्मेलन का उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन तथा पूर्व रक्षा राज्यमंत्री ब्रिगेडियर (अवकाशप्राप्त) के.पी. सिंहदेव ने किया। श्री सिंहदेव ने श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी के कार्यकाल से लेकर अब तक विभिन्न कांग्रेसी सरकारों द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए शुरु किए गए अनेक कल्याणकारी उपायों की चर्चा की तथा पूर्व सैनिकों को उनकी जानकारी दी। उन्होंने यूपीए चेयरपर्सन तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार द्वारा शुरु की गई अनेक योजनाओं तथा पेंशन लाभ का विवरण भी दिया।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कैप्टन प्रवीण दावर ने आजादी की लड़ाई तथा राष्ट्र निर्माण में प्रमुख कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही जनतंत्र, पंथनिरपेक्षता तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बुनियादी डाली गई थी।

सांप्रदायिक तथा जातिवादी राजनीतिक दलों की निंदा करते हुए कैप्टन दावर ने वसुंधरा राजे सरकार के कुशाल तथा अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के अच्छे कामों की तुलना की और पूर्व सैनिकों से आग्रह किया कि वे भ्रष्ट, अक्षम तथा गरीब विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके।

इस कार्यक्रम की यह विशेषता रही कि इसमें कारगिल युद्ध के वीर सूबेदार (अवकाश प्राप्त) दिगेन्द्र सिंह, महावीर चक्र विजेता, भी मौजूद थे। उन्होंने इस युद्ध में अपने कारनामों की चर्चा की जिनके फलस्वरूप उन्हें महावीर चक्र मिला।

इस सम्मेलन को सुनियोजित तरीके से नागौर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन श्री गणेश सुन्दर ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन मेजर आर.पी. सिंह के मार्ग निर्देश में आयोजित किया था। इसमें १००० से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की खबर को राज्य के इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया ने प्रमुखता दी।

प्रवीण दावर

ध्यान हटाया

लल्लोचप्पो का श्रेष्ठ रूप नकल है। हमें श्री आडवाणी को उनके हाल के संबोधन में नकली छवि के लल्लोचप्पो के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यहां एक व्यक्ति है जो जल्द प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन उन्होंने महसूस नहीं किया कि कांग्रेस के प्रति उनकी शब्दावली में परिवर्तन हुआ है। एक उद्योग संगठन की बैठक में उन्होंने अपने हाल के संबोधन में प्रधानमंत्री बनने की जिज्ञासा को दोहराया। उन्होंने समायोजित विकास, जरूरतमंदों के लिए छात्रवृत्ति, कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिये जाने के बारे में कहा। ये सब "शाइनिंग इंडिया" से काफी दूर है। वह इन मोर्चों पर यूपीए की क्यों नकल कर रहे हैं। वे भूल गये हैं कि वह और उनकी पार्टी बाद में बनी है। उन्होंने इन मोर्चों पर कभी कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की दार्शनिकता का अनुसरण कर रहे हैं। उनकी आलोचनाएं तत्यव, हीन है।। वह प्रधानमंत्री-इन वेटिंग बनने से पहले क्या कर रहे थे। उनकी पार्टी छात्रवृति के लिए क्या कर रही थी। तथ्य चौंकाने वाले होंगे। मौजूदा सरकार ने कक्षा आठ से बारह के बच्चों को ७५० करोड़ रूपये की छात्रवृति आवंटित की है। वर्ष २००८-०६ के दौरान इस कार्यक्रम के तहत करीब एक लाख स्कूल कवर किये जायेंगे। जब एनडीए सरकार सत्ता में थी तो यह प्रतिभाशाली योजना उनके दिमाग में क्यों नहीं आई। पिछले साल शिक्षा के लिए आबंटन में ३३ प्रतिशत की वृद्धि की गई। इस साल यह पिछले साल से २० प्रतिशत अधिक आवंटित की गई। लेकिन भाजपा के बजट में शिक्षा के लिए इतनी बड़ी राशि का कभी भी प्रावधान नहीं किया गया।

विफल प्रदर्शन

राजग द्वारा 'भारत बंद' का आह्वान पूर्णरूप से विफल रहा। गर्म मौसम के कारण कुछ दुकानें बंद रही लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बंद के कारण हम तीन महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। सबसे पहले जिन राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं है उन्हें भारत बंद जैसे आंदोलन का आह्वान नहीं करना चाहिए। इसने उनका पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया जो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन को पुनर्जीवित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर-इन-वेटिंग श्री लाल कृष्ण आडवाणी के लिए यह एक और अवसर हो लेकिन उनके घटक दलों ने इस आह्वान का समर्थन नहीं किया और इसके दूर रहे। इस मुद्दे पर भाजपा अलग-थलग पड़ गई। इससे हतोत्साहित होकर जैसा कि आप लोगों ने कुछ समाचार पत्रों में देखा होगा, आडवाण ाी एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं। श्री तिवारी ने कहा कि जनता महंगाई को लेकर चिंतित है और केन्द्र सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए हर प्रकार के उपाय कर रही है और इस मुद्दे को लेकर जनता तथा आम आदमी इसका राजनीतिकरण न करें।

भयंकर त्रासदी

श्री मनीष तिवारी ने कहा कि हम कल जयपुर में भयंकर राष्ट्रीय त्रासदी के बाद मिल रहे हैं। दर्जनों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महिलाएं और बच्चें मारे गये। कमाने वाले व्यक्ति को उनके परिवार से छीन लिया गया। कांग्रेस पार्टी इस भयंकर दुखद त्रासदी में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के साथ है। भारत को आतंकवाद से भयभीत नहीं किया जा सकता और निर्दोष नागरिकों को लक्ष्य बनाकर इस घिनौनी हरकत से हम डरनेवाले नहीं हैं। त्रासदी का आत्मविश्लेषण करने का एक समय भी है। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ विशिष्ट कार्रवाई के वक्त एक केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा संघीय जांच के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास किया है। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ राज्यों ने राज्य के दूसरे कोने में और देश के पार आतंकवाद की दलीलें देकर इसका विरोध किया है। हम विभिन्न राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि समय का तकाजा है कि वे अपने रूख पर विचार करें। आतंकवाद की महाविपत्ति से निपटने के लिए सभी राष्ट्रीय संसाधनों की लामबंदी जरूरी है।

घृणित आरोप

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अरूण जेटली द्वारा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के खिलाफ लगाये गये घृणित और अपमानजनक आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद समझती है। आतंकवाद जैसे ज्वलंत मुद्दे भी निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की नीयत पर प्रश्नचिन्ह लगाना भारतीय राष्ट्र के अधिकार को प्रत्येक रूप से चुनौती देना जैसा है। यह ऐसा आरोप है जो सीमापार और अन्य स्थानों के विध्वंसकारियों को बढ़ावा देगा, जो भारत की आर्थिक प्रगति, शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने पूरी तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी के दायित्व को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री की नीयत पर प्रश्नचिन्ह लगाकर सबसे खतरनाक, विघटनकारी और अपने घिनौना रवैये का परिचय दिया है। वह एक जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी की साख को गवां चुकी है।

यूपीए के चार वर्ष

श्री अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी ईर्ष्या की गंभीर बीमारी से अंगूर खट्टे हैं की तरह ग्रस्त है। उनके पास यूपीए के शासन के चार वर्ष की उपलब्धियों को स्वीकार करने की उदारता नहीं हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार की उपलब्धियों पर कांग्रेस पार्टी को गर्व है। यूपीए सरकार ने काफी न्यूनतम साझा कार्यक्रम को पूरी भावना के साथ क्रियान्वनित किया है। थोड़ा बहुत जो शेष भी है उसे यह अपनी बकाया अवधि के दौरान सक्रियता से क्रियान्वनित करने पर ध्यान देगी। जहां तक हमारा पक्ष है उपदेश और व्यवहार के बीच कोई अंतर नहीं है। लंगड़ी बैसाखी जैसे उपनाम का उपयोग और बुलाने से पहले भाजपा को आत्मविश्लेषण और सोचना चाहिए राजग सरकार का छह साल का कार्यकाल उस बत्तख जैसा है जिसने कभी अंडे नहीं दिये। राजग ने छह वर्ष पूरे किए और वह इंगलिश मुहावरे की तरह एक बड़े शून्य की तरह एक बत्तख बन कर रही। मैंने पूछता हूं कि राजग ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी बिल जैसी अनूठी क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने क्यों नहीं कभी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में सोचा? क्या उसने कभी राष्ट्रीय शहरी जीर्णोद्धार मिशन का स्वप्न देखा? क्या उसने भारत निर्माण की खोज की?

– टॉम वडक्कन,
सचिव, एआईसीसी

1

2

3

4

5

6

7

१. यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील, उपराष्ट्रपति मुहम्मद हामिद अंसारी तथा प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह २१ मई, २००८ को वीर भूमि पर राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए।

२. कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर २७ मई, २००८ को नयी दिल्ली में आयोजित भजन कार्यक्रम में शामिल हुईं। समारोह में उपराष्ट्रपति मुहम्मद हामिद अंसारी तथा दिल्ली के उपराज्यपाल श्री तेजिन्दर खन्ना भी शामिल हुए।

३. प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह ने ११ जून, २००८ को नयी दिल्ली में स्व. राजेश पायलट के यादगार में डाक टिकट जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तथा केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए. राजा भी इस मौके पर मौजूद थे।

४. यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने २१ मई, २००८ को नयी दिल्ली में ब्रूनेई के सुल्तान हाजी हसनाल बोल्कैया वद्दौला से भेंट की।

५. केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने १६ जून,२००८ को नयी दिल्ली में गंदी बस्तियों के लोगों के लिए लघु ऋण स्कीम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित भी मौजूद थीं।

६. महिला कांग्रेस अध्यक्ष डा० प्रभा ठाकुर श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर अ.भा. कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित निश्शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर को संबोधित कर रही हैं। इस मौके पर अ.भा. कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री मोतीलाल वोरा तथा श्रीमती मोहसिना किदवई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी।

७. हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा तथा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री फूलचन्द मुल्लाना को गोहाना तथा इन्द्री विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की खुशी में माला पहना रहे हैं।